सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh
Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 1, अंक 103, नई दिल्ली, गुरुवार, 09 फरवरी 2023, पेज 8

NEWS NTV TRANSPORT VISHESH
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये
परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

● 03 सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को जारी किया नोटिस
● 05 BMW ने X5 और X6 को किया ग्लोबली रिवील
● 08 क्या सरकार करेगी 6000 रुपये की राशि में इजाफा?

आज का सुविचार

"बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, सबसे आगे सोचो, विचारों पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है।

देश का पहला हाईटेक दिल्ली-मुम्बई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, एक हिस्सा 12 को होगा शुरू, जानें खासियत

सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की उपस्थिति में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी

संजय बाटला

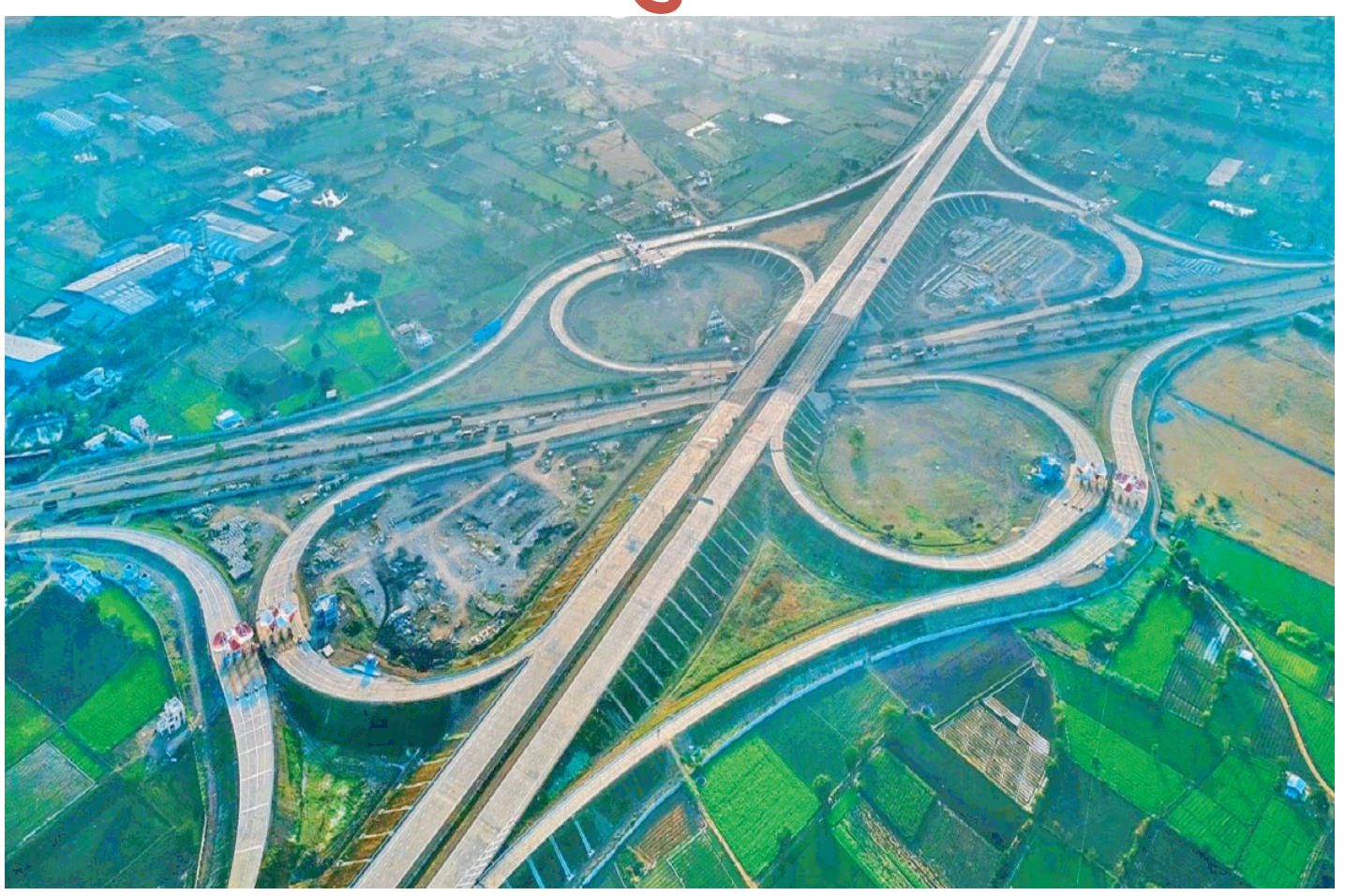

नई दिल्ली। आने वाले साल में आप एक बार जरूर सड़क से दिल्ली से मुम्बई तक की यात्रा करना चाहेंगे. एक लाख करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय बन रहे दिल्ली-मुम्बई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के जरिए 1382 किमी की दूरी केवल 12 घंटे में तय होगी. आठ लेन की सड़क का यह सफर ना थकाऊ होगा और ना ही ऊबाउ. कारण, दिल्ली से आगे चलते ही हरे-भरे खेत, धूप-छांव की आंख मिचौली खेलते पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एसे चार टाइगर रिजर्व से गुजरेंगे, जहां जाने के लिए हम कई बार योजना बनाकर भी नहीं जा पाते. रास्ते में पर्यटन का आनंद और अलग-अलग व्यंजनों का स्वाद लेते हुए यह सफर कब पूरा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा.

आठमार्च 2019 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी. इस एक्सप्रेस-वे की संकल्पना कुछ तरह थी कि वह पिछड़े क्षेत्र जो मुख्य मार्ग से दूर हैं, उन्हें जोड़ा जाए. सड़क को इस तरह बनाया जाए, जिसमें आधुनिक तकनीक का समावेश हो. कम लागत में एसा उम्दा मार्ग बनाया जा रहा जो समय और ईंधन दोनों की बचत करेगा.

एक हिस्से में इलेक्ट्रिक हाईवे बनेगा

इस एक्सप्रेस-वे के एक हिस्से को ई-हाईवे (इलेक्ट्रिक हाईवे) के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां ट्रक और बसें 120 किमी प्रतिघंटे की गति से चलेंगे, जिससे लॉजिस्टिक लागत में 70 फीसदी की कमी आएगी. पूरे एक्सप्रेस-वे को पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. जिसमें 20 लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं, प्रत्येक 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन प्रणाली के साथ पूरे खंड में ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था की गई है. इस एक्सप्रेस-वे में हर साल 32 करोड़ लीटर से अधिक डीजल-पेट्रोल की बचत होगी. जिससे करीब 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाईआक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी.

जहां जानवरों के लिए ओवरपास

यह एशिया का पहला एक्सप्रेस-वे होगा, जहां जानवरों के लिए ओवरपास बनाए जा रहे हैं. यह एक्सप्रेस-वे चार टाइगर रिजर्व रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा नेशनल पार्क और रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बीच से गुजरेगा. यहां दोनों ओर 8 मीटर लंबी शोर अवरोधक दीवारें तथा 6 फुट ऊंची दीवारें होंगी, जिससे जानवर सड़क पर और यात्री जंगल में नहीं जा सकेंगे. यह यात्रा लोगों को नई अनुभूति देगी.

इसी एक्सप्रेसवे से विश्व रिकार्ड भी बना

यह एक्सप्रेस-वे कई दृष्टि से खास है. क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि जिस भारत में गड्ढों में सड़क तलाशी जाती थी, वह भारत सड़क निर्माण में विश्व रिकार्ड भी बनाएगा, लेकिन यह कीर्तिमान स्थापित हुआ गुजरात में. आप जब दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे से गुजरेंगे तो बड़ौदा के हुसैपुर-सादणगांव और भरूच से 20 किमी दूर कैलोद गांव के पास 24 घंटे में ढाई किमी की 4-लेन सीमेंट कंक्रीट की उसी सड़क से गुजरेंगे, जिसने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है. गुजरात में पटेल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा यह रिकार्ड कायम किया गया है. एक फरवरी 2021 को सुबह 8 बजे शुरू हुआ काम अनवरत 24 घंटे चला और 2 फरवरी को जब सूर्योदय हुआ तो सड़क निर्माण के कीर्तिमान की वह लालिमा बिखेर रहा था.

एक्सप्रेस-वे में 94 वे-साइड एमेनिटीज

इतने लम्बे सफर में चलने वाला किसी एसी जगह पर ठहरना चाहता, जहां सुकून हो. वह ऐसे स्थान पर रुकना चाहता है, जहां स्वादिष्ट व्यंजन हों, आनंद हो और आराम हो. इस एक्सप्रेस-वे में इसका खास ध्यान रखा गया है. इस पूरे एक्सप्रेस-वे में 94 वे-साइड एमेनिटीज बनाई जा रही हैं. जहां ठहरने के लिए मोटल होगा. खाने के लिए उम्दा किस्म के रेस्त्रा होंगे. चाइल्ड केयर रूम होगा. सर्विस सेंटर, पेट्रोल पंप, एटीएम के अलावा एक छोटा हाट-बाजार होगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकल फॉर वोकल की नीति को अपनाया गया है. इसके लिए प्रत्येक वे-साइड एमेनिटीज में उस क्षेत्र में उत्पादित सामान का स्टाल भी होगा.

कई राज्यों में आने जाने का सुगम साधन बनेगा

यह एसा एक्सप्रेस-वे है जो केवल पांच राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मप्र, गुजरात और महाराष्ट्र को नहीं जोड़ेगा, बल्कि यह उप्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तक जाने का सुलभ साधन बनेगा. इसके लिए कई स्थानों पर इंटरचेंज दिया जा रहा है. उप्र में बन रहे नए जेवर एयरपोर्ट को इस एक्सप्रेस-वे से कनेक्ट किया जा रहा है. चंबल एक्सप्रेस-वे के जरिए कोटा से इटावा को कनेक्ट किया जाएगा. आगरा-जयपुर के बीच सम्पर्क मार्ग बनाया जा रहा है. इंदौर से उज्जैन होकर कोटा तक नया कॉरिडोर बन रहा है, इसमें दौसा से बाड़मेर तक नया मार्ग बनाकर अमृतसर-जामनगर कारिडोर से जोड़ा जा रहा है, जो पंजाब तक जाने का सीधा मार्ग बनेगा. यही कॉरिडोर हमें दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे से जोड़ेगा, जो वैष्णव देवी की यात्रा को सुगम बनाएगा.

प्रधानमंत्री करेंगे देश को समर्पित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक 246 किमी, 8-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का पहला हिस्सा देश को समर्पित कर रहे हैं. यह पूरा एक्सप्रेस-वे 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा. देश का पहला सबसे लम्बा एक्सप्रेस-वे भारत के सामाजिक, आर्थिक बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

इनसाइड

रोडवेज बसों का सफर हुआ महंगा 40 हजार यात्रियों की जेब ढीली

बागपत। परिवहन निगम ने बसों का किराया बढ़ा दिया है। उसके मुताबिक जिन रूटों पर टोल टैक्स है, उन पर बसों का किराया ज्यादा बढ़ा है। सामान्य बसों का किराया अब एक रुपये पांच पैसे से बढ़ाकर एक रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर रखा है। उधर, यात्रियों का कहना है कि महंगाई से आमजन पहले से ही परेशान है। ऐसे में किराया बढ़ाना गलत है। बड़ौत डिपो के अनुसार निगम की 59 और 48 बसें अनुबंधित हैं। जिनमें रोजाना लगभग 40 हजार यात्री सफर करते हैं। बस संचालन प्रभारी नरेंद्र मान ने बताया कि बड़ौत-शामली मार्ग पर जिवाना के समीप टोल टैक्स है। उन पर बसों का किराया बढ़ाए गए किराए से सात रुपये अतिरिक्त यात्रियों से वसूला जाएगा। जिन रूटों पर टोल टैक्स नहीं है उन पर सामान्य किराया देना पड़ेगा। बताया कि पहले सामान्य बसों का किराया एक रुपये पांच पैसे था। अब एक रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर रखा है।

सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से फोरलेन परियोजनाओं के निर्माण में गति देने का किया आग्रह

एनटीवी संवाददाता

शिमला। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश की फोरलेन परियोजनाओं विशेषकर किरतपुर-मनाली, परवाणू-शिमला, चक्की-मटौर-शिमला, मंडी-पठानकोट, नालागढ़-स्वारघाट, मुबारकपुर-अंब-नादौन और पावंटा साहिब-कालाअंब राजमार्ग के निर्माण कार्यों को गति दी जाए, जिससे इनका कार्य समयबद्ध पूर्ण हो सके।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और प्रदेश से संबंधित विभिन्न मामलों विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से कार्यान्वित की जा रही फोरलेन परियोजनाओं और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश की फोरलेन परियोजनाओं विशेषकर किरतपुर-मनाली, परवाणू-शिमला, चक्की-मटौर-शिमला, मंडी-पठानकोट, नालागढ़-स्वारघाट, मुबारकपुर-अंब-नादौन और पावंटा साहिब-कालाअंब राजमार्ग के निर्माण कार्यों को गति दी जाए, जिससे इनका कार्य समयबद्ध पूर्ण हो सके। उन्होंने टू लेन हाईवे को फोरलेन में स्तरोन्नत करने और राष्ट्रीय राजमार्गों में टनल निर्मित करने के संबंध में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुचारू यातायात तथा यात्रियों की सुविधा के लिए फ्लाई ओवर निर्माण तथा पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे के निर्माण का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य में आगामी पर्यटन सीजन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत कार्य के लिए धनराशि जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकतर पर्यटक सड़क मार्गों से आते हैं और इसे ध्यान में रखते हुए सड़क मार्गों को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्यान्वित की जा रहीं केंद्र की ओर से वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने अंतरराज्यीय संपर्क सुविधा के उन्नयन पर भी बल दिया और केंद्रीय मंत्री ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के संबंध में उठाए गए विभिन्न मामलों पर केंद्रीय मंत्री की ओर से हरसंभव सहायता और सहयोग के लिए आश्वासन दिया गया है।

गडकरी ने कहा- ड्रोन से जल्द भेजी जा सकेगी मिसाइल, बड़े स्तर पर चल रही है रिसर्च

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को नितिन गडकरी ने सुझाव दिया कि अभी ड्रोन में लिथियम बैटरी से चलने वाले इंजन का प्रयोग हो रहा है। इसमें फ्लैक्सिबल इंजन का प्रयोग होना चाहिए, जिसमें बैटरी के साथ ईधन के रूप में इथेनॉल का प्रयोग हो सके। इसके ड्रोन संचालन में आने वाला खर्च भी घटेगा, साथ ही अन्य लाभ भी होंगे।

देश में जल्द ही ड्रोन से मिसाइल भी भेजी जा सकेगी। ये दावा है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का। मंगलवार को दिल्ली के एक निजी होटल में स्काई यूटीएम (अनमेन ट्रैफिक मैनेजमेंट) को लॉन्च करते हुए मंत्री ने कहा कि डिफेंस में मिसाइल को ले जाने वाले ड्रोन बनाए जा रहे हैं।

ड्रोन भविष्य में काफी मददगार साबित होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में सामान की ढुलाई के लिए कारगर रहेगा। ड्रोन तकनीकी में सुधार के लिए बड़े स्तर पर रिसर्च चल रही है। देश में ड्रोन पोर्ट भी बनाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ड्रोन के माध्यम से सड़कों का ऑडिट भी किया जाएगा। ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को नितिन गडकरी ने सुझाव दिया कि अभी ड्रोन में लिथियम बैटरी से चलने वाले इंजन का प्रयोग हो रहा है। इसमें फ्लैक्सिबल इंजन का प्रयोग होना चाहिए, जिसमें बैटरी के साथ ईधन के रूप में इथेनॉल का प्रयोग हो सके। इसके ड्रोन संचालन में आने वाला खर्च भी घटेगा, साथ ही अन्य लाभ भी होंगे।

स्काई यूटीएम के सीईओ अंकित कुमार ने कहा कि यह एक ऐसा प्लेटफार्म है, जिसमें सभी ड्रोन संचालकों को पंजीकरण कराने के बाद संचालन से जुड़ी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। अभी तक गूगल मैप सहित अन्य का सहारा लेना पड़ता था। उन्होंने कहा कि हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ड्रोन के संचालन पर पूरी नजर रखेंगे। संचालक को बताएंगे कि वह कहां, कैसे, किस रूट पर और कब ड्रोन को उड़ा सकते हैं। ड्रोन के लिए लाइसेंस लेने से लेकर अन्य सभी मदद भी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे एडवांस सुविधा है। अभी हमारे साथ 20 से अधिक कंपनियां जुड़ी हुई हैं।

राज्यों और नेशनल हाईवे निर्माण से संबंधित एजेंसियों के लिए हाल में जारी एक सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा

बड़े पुलों और ओवरब्रिज पर फुटपाथ की व्यवस्था जरूरी, सुगम यातायात के लिए परिवहन मंत्रालय ने जारी किया आदेश

एनटीवी संवाददाता

सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने नेशनल हाईवे से लगती सर्विस और स्लिप रोड के निर्माण में भी इसके प्रयोग को अनिवार्य बना दिया है। इससे सड़क की मजबूती भी बढ़ती है।

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुगम यातायात तथा सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों तथा ओवरब्रिज के निर्माण में इसके प्रति खास तौर पर ध्यान देने लिए कहा है कि सभी बड़े पुलों पर फुटपाथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। इसी तरह छोटे पुलों पर केवल बिल्ट-अप एरिया में फुटपाथ उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

बड़े पुलों पर जरूर बने फुटपाथ

राज्यों और नेशनल हाईवे निर्माण से संबंधित एजेंसियों के लिए हाल में जारी एक सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा है कि अलग-अलग साइट स्थिति के आधार पर पुलों की अलग-अलग चौड़ाई की जरूरत होती है, लेकिन यह जरूरी है कि पुलों की चौड़ाई और उसमें फुटपाथ की अनिवार्यता का सही तरह पालन किया जाए। अगर पुल पर फुटपाथ बनाया गया है तो यह आवश्यक है कि बाहरी किनारे से उसकी चौड़ाई डेढ़ मीटर जरूर हो तथा अंदरूनी छोर पर क्रैश बैरियर भी होना चाहिए है।

सर्विस रोड के लिए प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल

सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने नेशनल हाईवे से लगती सर्विस और स्लिप रोड के निर्माण में भी इसके प्रयोग को अनिवार्य बना दिया है। पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्र में नेशनल हाईवे के 50 किलोमीटर दायरे में सर्विस और स्लिप रोड के निर्माण में ऊपरी सतह हाटमिक्स बिटुमिन कोट में प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है।

अनिवार्य रूप से हो प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल

मंत्रालय ने एनएचएआइ तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से जुड़ी एजेंसियों से कहा है कि एनएच तथा केंद्रीय सहायता प्राप्त सड़क निर्माण की जिन परियोजनाओं के लिए अभी निविदाएं नहीं आई हैं, उनमें प्लास्टिक कचरे का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाए। प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल के कारण तारकोल की जरूरत में 15 से 20 प्रतिशत की कमी आती है। इससे सड़क की मजबूती भी बढ़ती है और उसकी मरम्मत की जरूरत भी अपेक्षाकृत देर से महसूस होती है।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

फीमेल ऑर्गेज्म से जुड़े हैं ये 5 अज्ञात फैक्ट्स, जानकर आप भी हो जाएंगी हैरान

महिलाओं के शरीर से जुड़े फैक्ट्स
महिलाओं को खुद पता नहीं होते हैं. उन्हें अपने शरीर के बारे में समझने की जरूरत है, खुलकर बात करने की जरूरत है, न की इस पर चुप रहने की. सेक्स जरूरी है और इससे जुड़े अंग जो आपको उत्तेजित करते हैं उसके बारे में जानना भी जरूरी है. आज हम 5 ऐसे ही अज्ञात तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होने वाली है'

महिलाओं में 3 से अधिक यौन अंग होते हैं !
महिला के बाहरी यौन अंग को लेबिया मेजोरा कहा जाता है. यह योनि के खुलने के आसपास वाली त्वचा होती है, जो 2 फोल्ड्स में मौजूद होती है. भीतरी यौन अंग को लेबिया माइनोरा कहा जाता है, जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होते हैं. आंतरिक महिला यौन अंग में अंडाशय (Ovaries), फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय (Uterus), गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) और योनि (Vagina) हैं. महिला सेक्स सिर्फ प्रजनन (Reproductive) अंग नहीं हैं, वे महिलाओं में यौन उत्तेजना का भी काम करते हैं.

विभिन्न चरणों में समझे फीमेल ऑर्गेज्म
जिस तरह से एक महिला को ऑर्गेज्म प्राप्त होता है वह पुरुषों की तुलना में अलग होता है. पहले एक उत्तेजना चरण होता है जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होता है. दूसरा जब क्लाइटोरिस प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है. क्लाइटोरिस को "फीमेल पेनिस" भी कहते हैं, जो महिलाओं के शरीर का सबसे ज्यादा उत्तेजित करने वाला अंग माना गया है. तीसरा चरण ऑर्गेज्म से ठीक पहले होता है जहां हृदय गति सबसे अधिक होती है. अंतिम चरण रिलीज या संभोग का चरण है.

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 8,000 से अधिक तंत्रिका हैं. इस प्रकार से यह सबसे अधिक उत्तेजना उत्प्रेरण अंगों में से एक है. ऐसा कहा जाता है कि 75 प्रतिशत से अधिक महिलाओं में क्लाइटोरिस को छूने पर ही ऑर्गेज्म चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है. तीन-चौथाई क्लाइटोरिस छिपे हुए होते हैं शायद इसीलिए इसे कामोत्तेजना वाले अंग के रूप में नहीं देखा जा सकता है. क्लाइटोरिस का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को आनंद देना होता है.

फीमेल ऑर्गेज्म में स्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

महिलाओं में स्तन और निप्पल की उत्तेजना के कारण भी ऑर्गेज्म प्राप्त किया जा सकता है. अध्ययनों से पता चला है कि निप्पल को उत्तेजित करने से भी जेनाइटल्स यानी जननांगों को सक्रिय किया जा सकता है.

महिला को आनंद देने वाले अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं

महिलाओं को सुख देने वाले अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एक अंग से प्रत्येक अंग उत्तेजित होता है. जिस वजह से महिलाओं को अधिक आनंद की प्राप्ति होती है. पार्टनर की प्राथमिकता, पसंद और सेक्सुअल एनाटॉमी को ध्यान में रखें. इंटरकोर्स यानी संभोग के दौरान यह महत्वपूर्ण होता है.

महिलाओं में होने वाली हेल्थ से जुड़ी परेशानियां, जिनके बारे में जानना है बेहद जरूरी

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कुछ अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की संभावना अधिक रहती है लेकिन समय पर इलाज होने पर उपचार संभव है. जानिए महिलाओं में होने वाली कुछ सामान्य हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के बारे में. क्या आप जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक डेथ्स की संभावना अधिक होती हैं. यही नहीं, डिप्रेशन और एंग्जायटी की समस्या भी महिलाओं में अधिक देखी जाती है. महिलाओं और पुरुषों दोनों कई हेल्थ कंडिशंस से गुजरते हैं लेकिन कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, जो महिलाओं में ज्यादा देखी जाती हैं. वहीं जानकारी की कमी या लापरवाही के कारण कई महिलाओं की हेल्थ कंडिशंस का समय पर निदान नहीं हो पाता.

छात्राओं का बढ़ता यौन उत्पीड़न रोकें

छात्राओं का यौन उत्पीड़न शिक्षा समाज में एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसे राज्य सरकारें कभी भी हल्के से न लें। क्यों न हमारे पत्रकार दोस्तों और सरकारों द्वारा यह पड़ताल की जाए कि राज्यों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी व कोचिंग सेंटर्स में छात्राओं की अस्मत की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं। कहीं पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटना होने पर शिक्षा संस्थानों पर तुरंत वाजिब एक्शन लोकहित में होना चाहिए'

डा. वरिंदर भाटिया

देश के अनेक राज्यों के शिक्षा संस्थानों मे छात्राओं का यौन शोषण चिंताजनक बनता जा रहा है। इसी संदर्भ में हाल ही में कोचिंग सेंटरों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि सभी कोचिंग संस्थानों को छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रभावी क़दम उठाने के निर्देश दिए जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग सेंटरों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 और इसके तहत दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से अमल सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें। आयोग ने कहा है कि हाल के सालों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन गया है। आयोग कोचिंग/शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर चिंतित है। आयोग ने सभी हितधारकों के बीच कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए भी कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम की जगह पर यौन उत्पीड़न के मामले जिम्मेदारी और प्रभावी ढंग से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि ये कोचिंग सेंटर संबंधित प्राधिकरण में पंजीकृत हों और केंद्रों को चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की गई हो।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) विधेयक 2012 (संशोधित विधेयक) संसद द्वारा 2013 में पारित किया गया था। यौन उत्पीड़न कानून संगठित और असंगठित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। हमारी जानकारी के लिए, किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी लालच देकर अनावश्यक रूप से दबाव बनाना भी यौन शोषण अपराध का हिस्सा होता है। कार्यस्थल पर अश्लील चित्र दिखाना, शरीर के यौन अंग पर टिप्पणी करना, यौन गतिविधियों की अफवाह फैलाना, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी महिला के साथ अभद्रता या गाली गलौज करना भी यौन शोषण के अंतर्गत आता है। शिक्षा के मंदिर इसका अपवाद नहीं हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं की तुरंत रिपोर्टिंग की जरूरत होती है परन्तु छात्राओं द्वारा किन्हीं कारणों से इसको न बताने पर उनका शोषण बढ़ता जाता है। बेहतर है सरकारें छात्राओं से मिली इस जानकारी को गुप्त रख छद्म जांच करें और कार्रवाई करें। कुछ समय से देश के अनेक राज्यों में छात्राओं के यौन शोषण की घटनाओं में बढ़ोतरी से सामाजिक व्याकुलता बढ़ रही है। यौन शोषण का छात्राओं के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जिस मनुष्य का यौन शोषण हुआ होता है वह पूरी मानवता से नफरत करने लगता है। उसे हर व्यक्ति केवल शोषण करने वाला ही दिखता है क्योंकि यह उसकी मानसिकता बन जाती है जिसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है और उसके लिए बहुत सी तकलीफों का सामना भी करना होता है, जैसे कि वह यौन शोषण उसे बार-बार याद आते रहते हैं और उसको और ज्यादा मानसिक तकलीफ होती है जो उसके लिए बहुत कष्टदायक होती है, यह जिस तन लागे वोही जाने वाली स्थिति होती है। आज सिर्फ कोचिंग सेंटर ही नहीं, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कुछ समय पहले एक छात्र ऑडिट के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 24 कॉलेजों और विभागों में सर्वेक्षण किया गया। कुल 810 छात्र-छात्राओं ने सवालों के जवाब दिए। इसमें करीब 90 प्रतिशत महिलाएं और 10 प्रतिशत पुरुष थे। रिपोर्ट में कहा गया कि हर चार छात्राओं में से एक ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की। यौन उत्पीड़न के 188 मामलों में 40 मामले शारीरिक उत्पीड़न के थे। उत्पीड़न के पांच में से एक मामला जबरदस्ती छूने या पकड़ने का था। उत्पीड़न के प्रत्येक पांच मामलों में से एक सोशल मीडिया पर ट्रोल करने या कॉल या लिखित वॉट्सऐप मैसेजों के जरिए उत्पीड़न का था।

जवाब देने वाले तकरीबन 80 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने परिसर में असुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन की ओर से कदम नहीं उठाने को जिम्मेदार ठहराया। ऐसा ऑडिट सरकारों की तरफ से सभी कॉलेजों में करवाया जाना चाहिए। सच बोलें तो सिर्फ छात्राएं ही नहीं, अमूमन सभी लड़कियों की लाइफ बहुत टफ होती है। उन्हें हर कदम पर न जाने कितनी गंदी नजरों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर उन्हें खुद को सुरक्षित रखने की चिंता लगी रहती है। ऑफिस या स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, अब तो लड़कियां घर तक पर सेफ नहीं हैं। आए दिन पिता या भाई द्वारा भी रेप की खबरों से सोशल मीडिया भरा रहता है। ऐसे माहौल में आप भी समझ सकते हैं कि यौन उत्पीड़न की वजह से लड़कियों के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया है। कॉलेज की बात करें तो वहां पर भी लड़कियों को यहां तक कि तदर्थ महिला अध्यापकों को भी पक्की जॉब के लिए यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। कई प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल रहते हैं जो बेडरूम सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। यह एक न हजम होने वाली सच्चाई हो सकती है। छात्राओं के यौन शोषण को लेकर विदेश की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। ब्रिटेन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आता है लेकिन पिछले कुछ समय पहले की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यहां पर छात्राओं का यौन उत्पीड़न सबसे ज्यादा होता है। कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों का यौन उत्पीड़न किया जाना ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में महामारी के स्तर तक पहुंच चुका है। वहां की कई यूनिवर्सिटियों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कर्मचारियों को विद्यार्थियों पर यौन संबंध के लिए दबाव बनाने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, ऐसा होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी पर्याप्त नियम नहीं हैं। बस इसी बात से आप जान सकते हैं कि जब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में लड़कियों और स्टूडेंट्स का ये हाल है तो फिर बाकी कॉलेजों में स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा होगा। एक जमाने में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को विद्या का मंदिर समझा जाता था और आज अपने देश में भी इनमें से कुछ की छवि इतनी ज्यादा धूमिल हो गई है कि अब इन्हें विद्या का मंदिर नहीं कहा जा सकता है। राज्य सरकारें ऐसे इंतजाम करें, ऐसे रिपोर्टिंग सिस्टम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कहें जिससे छात्राओं के यौन शोषण के मामले दबे नहीं।

छात्राओं का यौन उत्पीड़न शिक्षा समाज में एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसे राज्य सरकारें कभी भी हल्के से न लें, क्यों न हमारे पत्रकार दोस्तों और सरकारों द्वारा यह पड़ताल की जाए कि राज्यों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर्स में छात्राओं की अस्मत की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं। कहीं पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटना होने पर शिक्षा संस्थानों पर तुरंत वाजिब एक्शन लोकहित में होना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि छात्राओं की पढ़ाई-लिखाई को उत्साह देने के लिए उन्हें सुरक्षित अकादमिक माहौल दिया जा सके। छात्राओं के हॉस्टल उनके लिए कितने सुरक्षित हैं, यह वैरिफिकेशन जरूरी और तुरंत हो तो बेहतर है। छात्राओं को सुरक्षित करना ही होगा।

मां बनने के बाद छोटी-छोटी बातें भूलने लगी हैं, तो 'मॉमी ब्रेन' प्रॉब्लम से ऐसे करें बचाव

क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप मां बनने के बाद छोटी छोटी बातें भूलने लगीं हैं? कभी ऐसा हुआ हो कि आप कमरे में तेजी से गईं और वहां जाकर भूल गईं कि आप क यों कमरे में आईं या गाड़ी की चाबी हाथ में हैं और आप पूरे फ्लैट में चाबी ढूंढती रहीं? अगर आप ऐसी समस याओं से परेशान हो गई हैं तो यह अकेले आपकी ऐसी समस या नहीं है. दरअसल इस समस या को मॉमी ब्रेन के नाम से जाना जाता है. वेरीवेलफैमिली के मुताबिक एक स्टडी में पाया गया है कि बच्चे को जन म देने से मां का मस्तिष्क भी काफी प्रभावित होता है और कभी-कभी लंबे समय तक इसका असर कायम रहता है. ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने भी ये पाया गया है कि मां बनने से महिला के याददाश त क्षमता पर स थाई असर पड़ता है.

क्या है इस परेशानी की वजह?

कई शोधकर्ताओं ने माना कि ये परिवर्तन एक नई मां को अपने बच्चे की देखभाल करने की क्षमता को बढ़ाने का एक नेचुरल तरीका होता है. यह भी कहा जा सकता है कि मस्तिष्क में ये परिवर्तन दरअसल नई माताओं को बच्चे की जरूरतों को अपनाने और उन हें पूरा करने के लिए अहम होता है.

मॉमी ब्रेन से उबरने के उपाय

धैर्य रखें- शरीर में हुए इस बायोलॉजिकल बदलाव की वजह से आप खुद से परेशान हैं और इरिटेट हो जाती हैं आपको बता दें कि अगर आप थोड़ा धैर्य रखें और किसी भी काम को पूरा करने के लिए थोड़ा एक स ट्रा ट लान बनाएं तो मॉमी ब्रेन की समस या से उबर सकती हैं.

लिस्ट बनाएं- इस समस या से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने हर काम की लिस ट बनाएं. इसके लिए आप एक नोटबुक कैरी करें और जब भी कुछ याद आए तो उसे लिख लें. ऐसा करने से आप जरूरी चीजों को भूलेंगी नहीं.

प्लान बनाएं- आप पहले से चीजों के लिए प लान बनाएं और अपनी हर चीज को सही जगह पर रखने की आदत डाल लें. इससे आपका काम काफी आसान बन जाएगा. मसलन, आप अगर सुबह डॉक टर के पास जाने वाली हैं तो रात में ही सारा सामान तैयार रखें. आप चाभी, वॉलेट आदि हमेशा एक ही जगह पर रखें आदि.

पर्याप्त नींद जरूरी- नई मांओं की व यस तता 24 घंटे की होती है. लेकिन आपको कुछ इस तरह अपने रुटीन को फॉलो करना है कि आपकी नींद पूरी हो सके. इसके लिए आप परिवार के लोगों की मदद ले सकती हैं और बच चे के साथ ही सोने और जागने की रुटीन को फॉलो कर सकती हैं. भरपूर नींद आपके ब्रेन को रिलैक स करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर पाएगा.

ब्रेन को दें एक्स्ट्रा केयर- ब्रेन के लिए आप अपने खानपान पर ध यान दें और ब्रेन गेम खेलें. ब्रेन गेम आपके दिमाग को एक्टिव रखने का काम करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे. इसके अलावा, आप उन चीजों को डाइट में शामिल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो और भरपूर प्रोटीन हो.

ज्यादा वजन भी बन सकता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह, इन तरीकों से करें बचाव

हाई रिस्क प्रेगनेंसी के खतरे से खुद को बचाना है तो समय-समय पर अपनी जांच जरूर कराती रहें. इसके अलावा, जहां तक हो सके प्रेगनेंसी में तनाव से दूर रहें, भरपूर आराम करें और रोजाना योग जरूर करें. इन बातों का ध्यान रखकर आप इस खतरे से बच सकती हैं.

मां बनने का सपना हर महिला देखती है. लेकिन कई महिलाओं में सेहत से जुड़ी समस्याओं की वजह से उनकी प्रेगनेंसी कठिनायों से भरी होती है. कई बार तो उनके लिए प्रेगनेंसी जोखिम भरा हो जाता है और इससे मां और पेट में पल रहे बच्चे की जान तक जा सकती है. इसी जोखिम को 'हाई रिस्क प्रेगनेंसी' कहा जाता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में तकरीबन 5,29,000 महिलाओं की मौत गर्भावस्था के दौरान इन खतरों की वजह से हो जाती है. इसकी वजह खराब सेहत, बदलती लाइफस्टाइल, खान पान में लापरवाही को माना जाता है. यही नहीं, कई बार ऐसी समस्याएं किसी बीमारी या जेनेटिक डिजीज की वजह से भी हो सकती है.

हाई रिस्क प्रेगनेंसी की ये हैं बड़ी वजह

एनआईएच के मुताबिक अगर महिला को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है या वो एचआईवी पॉजिटिव है तो उसे प्रेगनेंसी में रिस्क की समस्या हो सकती है. अगर महिला का वजन ज्यादा है तो इससे हाई ब्लड प्रेशर, प्रीक्लेम्पसिया, गर्भकालीन मधुमेह, स्टिलबर्थ, न्यूरल ट्यूब दोष और सिजेरियन डिलीवरी की समस्या हो सकती है. इसकी वजह से जन्म के समय नवजात में हृदय रोग का खतरा 15% तक बढ़ सकता है.

किशोरावस्था और 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं में गर्भावस्था की वजह से प्रीक्लेम्पसिया और गर्भकालीन उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह बन सकता है. गर्भाशय में हुई कोई पुरानी सर्जरी की वजह से भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा हो सकता है. इसके अलावा, जुड़वा बच्चों और आईवीएफ द्वारा गर्भ धारण की प्रक्रिया भी महिलाओं में रिस्की प्रेगनेंसी की वजह हो सकता है.

हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचाव का तरीका

अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं तो समय-समय पर अपनी जांच कराती रहें. इसके अलावा, प्रेगनेंसी में तनाव से बचें, भरपूर आराम करें, रोजाना योग ध्यान करें, फ्रेश हवा में वॉक पर जाएं, हेल्दी खान पान करें और डॉक्टर की संपर्क में रहें.

इनसाइड

हिन्दू-मुस्लिम एकता की मिसाल बनी भारत जोड़ो यात्रा, अल्पसंख्यकों समेत अन्य वर्गों का मिला समर्थन

नई दिल्ली। सड़क के दोनों तरफ राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिल्लीवासी दिखे। यात्रा में हिन्दू-मुस्लिम एकता की मिसाल कायम होती दिखाई दी। भारत जोड़ो यात्रा 3.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ती हुई मंगलवार को उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई। सुबह 10 बजे शुरू हुई 2020 के हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों से गुजरी। यात्रा के स्वागत के लिए बनाए गए मंच से कांग्रेस और यात्रा के समर्थन में नारे गूंजते रहे। सड़क के दोनों तरफ राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिल्लीवासी दिखे। यात्रा में हिन्दू-मुस्लिम एकता की मिसाल कायम होती दिखाई दी। भीड़ अधिक होने की वजह दीवार, सीढ़ियां और मेट्रो स्टेशनों और घरों की छत पर खड़े होकर भी लोगों ने यात्रा को दिल्ली से विदा किया। भीड़ इतनी अधिक थी कि कई बार समर्थकों के कदम लड़खड़ाए, फिर भी यात्रा में शामिल होने के लिए दोबारा दौड़ लगाई। करीब तीन साल पहले हिंसा की आग में झुलसी उत्तर पूर्वी दिल्ली में यात्रा को अल्पसंख्यकों समेत सभी वर्गों का पूरा समर्थन मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक हिंसा के बाद भी राहुल गांधी ने उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की थी। कई जगह महंगाई के खिलाफ रोष जताते हुए लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि परेशानी इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस से उम्मीदें बढ़ गईं हैं।

पोस्टरों में भी दिखी नफरत की खिलाफत

नफरत के खिलाफ राहुल गांधी के संदेश का असर पोस्टरों में भी दिखा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सड़क के दोनों तरफ लगे पोस्टर में लिखा था, एकता का राज चलेगा, हिन्दू मुस्लिम साथ चलेगा। नफरत के बाजार में, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, के संदेश से समर्थकों का जोश और अधिक दिखा। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में समर्थक हिन्दू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते दिखे। जैन, सिख, हिन्दू और मुस्लिम सहित तमाम वर्ग के लोग भी यात्रा का गवाह बने।

युवक की धारदार हथियार से हत्या, शव को जलाया, यमुना किनारे मिली बॉडी, नहीं हुई शिनाख्त

पुलिस के मुताबिक सोमवार शाम को वजीराबाद थाना पुलिस को खबर मिली कि रामघाट, वजीराबाद , यमुना खादर में एक शव जला हुआ पड़ा है। खबर मिलते ही फौरन एक टीम मौके पर पहुंची। शव की पड़ताल करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव से कुछ दूरी पर झाड़ियों में काफी मात्रा में खून पड़ा हुआ था। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हत्यारों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर शव को जला दिया। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो लगभग 90 फीसदी जली हुई हालत में शव मिला। क्राइम टीम के अलावा एफएसएल की टीम को मौके पर बुला लिया गया। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सब्जी मंडी मोर्चरी भेज दिया है। घटना स्थल के पास से पुलिस को एक पेपर कटर व माचिस बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक सोमवार शाम को वजीराबाद थाना पुलिस को खबर मिली कि रामघाट, वजीराबाद , यमुना खादर में एक शव जला हुआ पड़ा है।

आप की मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को जारी किया नोटिस

दिल्ली में दिसंबर के शुरुआत में ही नगर निगम के चुनाव हुए थे और तब से अब तक तीन बार मेयर चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। लेकिन तीनों ही बार मनोनीत सदस्यों के मताधिकार के मुद्दे को लेकर सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने दिल्ली नगर निगम में सही तरीके से मेयर के चुनाव करवाने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

शैली ओबरॉय ने अदालत में उपराज्यपाल के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उपराज्यपाल विनय सक्सेना व अन्य लोगों को नोटिस जारी कर मनोनीत सदस्यों के मत अधिकार पर जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि दिल्ली में दिसंबर के शुरुआत में ही नगर निगम के चुनाव हुए थे और तब से अब तक तीन बार मेयर चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। लेकिन तीनों ही बार मनोनीत सदस्यों के मताधिकार के मुद्दे को लेकर सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। तीनों बार ही मेयर का चुनाव नहीं हो सका।

दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आज तक कभी भी निगम के मेयर चुने जाने के वक्त मनोनीत सदस्यों ने वोट नहीं दिया। इस बार ऐसा करके भाजपा कम सीटें होने के बावजूद अपना मेयर बनवाना चाहती है। वहीं आप के इस आरोप पर भाजपा का कहना है कि हर बार मनोनीत सदस्य देर से चुने जाते थे और इस बार जब चुन लिए गए हैं तो वह वोट क्यों न दें।

शराब घोटाले में व्यवसायी गौतम मल्होत्रा गिरफ्तार; ED ने कोर्ट से मांगी 14 दिन की रिमांड, फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब बनाने वाली बड़ी कंपनी ओएंसिस ग्रुप के डायरेक्टर गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है। गौतम पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने गौतम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड की मांग की। कोर्ट ने मल्होत्रा की ईडी कस्टडी रिमांड दिनों पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि गौतम मल्होत्रा पूर्व अकाली दल के विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे हैं।

मल्होत्रा को बुधवार को पकड़ा गया। इस मामले में बुधवार को ये दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले सीबीआई ने हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरांटला को गिरफ्तार किया था। बता दें कि छह जनवरी को शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी चार्जशीट दायर की थी। ईडी ने ये चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी। दूसरी चार्जशीट में ईडी ने 12 आरोपी बनाए थे। इसमें 12 अभियुक्तों के नाम थे, इनमें पांच गिरफ्तार व्यक्ति (विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा) और सात कंपनियां शामिल हैं।

महिलाओं ने मोटरसाइकिल चालक को बातों में उलझाया, फिर सोने की अंगूठी चुराकर हुईं नौ दो ग्यारह

एनटीवी संवाददाता

द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में लाल बत्ती पर चोरी और लूटपाट करने वाली महिलाओं का गिरोह सक्रिय है। एक घटना में महिला ने साथ चलने से मना करने पर एक युवक को इधर-उधर की बातों में उलझाया और फिर उनकी अंगूठी चुराकर फरार हो गई।

नई दिल्ली। द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में लाल बत्ती पर चोरी और लूटपाट करने वाली महिलाओं का गिरोह सक्रिय है। एक घटना में महिला ने साथ चलने से मना करने पर एक युवक को इधर-उधर की बातों में उलझाया और फिर उनकी अंगूठी चुराकर फरार हो गई।

पुलिस में की शिकायत

चोरी होने का पता चलने पर युवक ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आरोपित की पहचान के प्रयास में जुटी है।

जानें पूरा मामला

शिकायतकर्ता प्रिंस लैपटाप मरम्मत का काम करते हैं। इनकी अंबराही गांव में दुकान है। सोमवार की रात वह दुकान बंद करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। सेक्टर एक द्वारका लालबत्ती पर उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी। इसी दौरान वहां मौजूद दो महिलाएं इनके पास आ गई और किनारे चलने के लिए कहने लगी। प्रिंस ने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिलाएं उनके साथ अश्लील हरकत करने लगी। जब प्रिंस इनसे पीछा छुड़ाते हुए आगे बढ़े तो पीछे से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार ने कहा कि अपना सामान की जांच कर लो। महिलाएं बातों में लगाकर सामान चोरी करती हैं।

प्रिंस ने यह सुनकर मोटरसाइकिल रोकी और देखा तो पता लगा कि अंगुली में कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है और उनकी सोने की अंगूठी गायब है। प्रिंस दोबारा द्वारका सेक्टर एक के लालबत्ती पर आए लेकिन तब तक दोनों महिलाएं वहां से गायब हो गई थी। पीड़ित ने तुरंत फोन कर घटना की जानकारी पुलिस से की। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन करने के बाद पीड़ित की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया।

फीडबैक यूनिट: सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के एलजी ने मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की मांगी

सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट विजिलेंस विभाग को सौंप दी है, जिसके आधार पर सिसोदिया पर केस चलाने की अनुमति मांगी जा रही है। फीडबैक यूनिट सिसोदिया के ही अधीन काम कर रहा था।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई फीडबैक यूनिट को लेकर सीबीआई ने विजिलेंस विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके अनुसार मनीष सिसोदिया पर विपक्षी दलों में जासूसी करने का आरोप लगा है। अब इस मामले में सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम पर केस चलाने की अनुमति चाहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार माना जा रहा है कि इसीलिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गृहमंत्रालय के जरिए मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की अनुमति मांगी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी जिसका काम हर विभाग पर नजर रखना था। सरकार का कहना था इससे उनकी मंशा ये है कि विभागों के भ्रष्टाचार पर नजर रखी जा सके। हालांकि बाद में सरकार पर आरोप लगा कि इसके जरिए दिल्ली सरकार विपक्षी दलों के कामकाज पर नजर रख रही थी। बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। अब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट विजिलेंस विभाग को सौंप दी है, जिसके आधार पर सिसोदिया पर केस चलाने की अनुमति मांगी जा रही है। फीडबैक यूनिट सिसोदिया के ही अधीन काम कर रहा था।

भाजपा नेताओं की जासूसी करा रहे केजरीवाल, इस आरोप के बाद सिसोदिया पर कसेगा फंदा!

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार 2015 में अपनी स्थापना से ही अराजकता के साथ काम करती रही है। अब इसके प्रमाण भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति गलत नीयत से काम करती है और उनके दमन में विश्वास करती है... भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार उसके नेताओं की जासूसी करा रही है। इसके लिए सरकार के नियंत्रण में एक विशेष यूनिट बनाई गई है, जिसके अधिकारियों को केवल भाजपा के नेताओं की जासूसी करने के पीछे लगाया गया है। पार्टी ने इसे जनता के पैसे से सरकार की ताकत का अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा दुरुपयोग बताया है। पार्टी इस बारे में औपचारिक शिकायत दर्ज कर उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग करने पर भी विचार कर रही है।

चूंकि, इस कथित जासूसी यूनिट की स्थापना उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ही एक मंत्रालय के अधीन की गई थी, इसकी जांच की आंच सिसोदिया पर भी आ सकती है। यानी शराब घोटाले के बाद इस मामले में भी उनकी परेशानी बढ़ सकती है। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार 2015 में अपनी स्थापना से ही अराजकता के साथ काम करती रही है। अब इसके प्रमाण भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति गलत नीयत से काम करती है और उनके दमन में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से एक फरवरी 2016 को केजरीवाल सरकार ने एफबीयू (फीडबैक यूनिट) की स्थापना की थी। राजनीतिक विरोधियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, उपराज्यपाल कार्यालय, मीडिया हाउस, प्रमुख व्यापारियों ही नहीं, बल्कि न्यायाधीशों तक पर नज़र रखने के लिए की गई थी। सचदेवा ने कहा कि एफबीयू की स्थापना बिना प्रशासनिक एवं आर्थिक स्वीकृति लिए केवल अपने कैबिनेट की स्वीकृति के आधार पर कर दी गई। इसमें बिहार पुलिस से लाये गये 17 पुलिस एवं अन्य कर्मी रखे गये थे। इनका मुखिया एक सेवानिवृत्त सीआईएसएफ के डीआईजी को बनाया गया था। इस एफबीयू को एक करोड़ रुपये का स्थापना फंड दिया गया और इसको सीक्रेट सर्विस फंड का नाम दिया गया।

उन्होंने प्रश्न किया कि आखिर केजरीवाल को किसकी जांच करवानी थी, जिसके लिये गुप्त फंड बनाया गया। इस फंड से करोड़ों का फंड प्राइवेट जांच एजेंसियों को किया गया, साथ ही मुखबिर खड़े करने के लिये भी किया गया।

उठे थे सवाल

सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने इस यूनिट की स्थापना पर आपत्ति जाहिर की थी। इस आपत्ति पर सितंबर 2016 में जब अश्वनी कुमार सतर्कता निदेशक बने तो उन्होंने एफबीयू से काम का लेखा जोखा मांगा पर, वह अपने काम की कोई रिपोर्ट नहीं दे पाई। इसी बीच अगस्त 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश आ गया कि दिल्ली के सभी मामलों में उपराज्यपाल सर्वोच्च होंगे, तब केजरीवाल सरकार को एफबीयू स्थापना की फाइल तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग को भेजनी पड़ी। उन्होंने सतर्कता विभाग के रहते ऐसी नई संस्था बनाने पर आपत्ति करते हुए न सिर्फ फाइल रिजेक्ट कर दी, बल्कि सीबीआई जांच के भी आदेश दिये।

दिल्ली दंगों को लेकर कोर्ट की टिप्पणी, कहा- सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए हुई थी हिंसा

एनटीवी संवाददाता

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि संपत्तियों को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। कोर्ट ने 5 पर आरोप तय करने का आदेश दिया है।

पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में स्कूल, घर व दुकानें जलाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच लोगों पर आगजनी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने समेत कई आरोप तय करने का आदेश किया है। आरोपित फैसल फारूक, मोहम्मद परवेज, अशरफ अली, सोनू सैफी और अनीश कुरैशी के खिलाफ मामला आगे चलाने की मंजूरी कोर्ट ने प्रदान कर दी है।

कोर्ट की दंगों को लेकर तीखी टिप्पणी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपितों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। आरोपित फैसल ने भीड़ को ऐसा करने के लिए उकसाया। कोर्ट ने इन आरोपितों पर लगे हत्या के प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप को साक्ष्यों के अभाव में हटा दिया।

स्कूल और दुकानों में भीड़ ने लगाई थी आग

कोर्ट ने कहा कि इसमें पुलिस की तरफ से लापरवाही रही है, वह एमटीएनएल और बीएसईएस को हुए नुकसान को रिकार्ड पर नहीं ला पाई। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का विरोध कर रही भीड़ ने दयालपुर थाना क्षेत्र में 25 फरवरी 2020 को डीआरपी पब्लिक स्कूल और उसके आसपास मकानों व दुकानों में आग लगा दी थी। आरोप था कि दंगाई भीड़ ने पुलिस पर पथराव करने के साथ उन पर गोलियां चलाईं।

जानबूझकर संपत्ति को पहुंचाया नुकसान

जानबूझकर हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इस मामले में पुलिस ने पड़ोस के राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैसल फारूक के साथ मोहम्मद परवेज, अशरफ अली, सोनू सैफी और अनीश कुरैशी को आरोपित बनाया था। आरोप लगाया गया था कि इस राजधानी पब्लिक स्कूल पर दंगाई एकत्र थे और फैसल ने उन्हें उकसाया।

इस मामले में आरोपों के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पांचों पर साजिश रच कर घटना को अंजाम देने व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप तय करने का आदेश किया। फैसल पर लोगों को उकसाने का आरोप भी लगाया, लेकिन इसे छोड़ कर बाकी चार पर गैर कानूनी समूह में शामिल होने का आरोप लगाया।

हाईवे पर रील, हुड़दंग और फायरिंग करने वाले 23 गिरफ्तार, 24 घंटे में पुलिस की कार्रवाई; कई वाहन सीज

एनटीवी न्यूज

दिल्ली-मेरठ हाईवे पर सोमवार रात हुड़दंग मचा रहे 13 आरोपितों को मोदीनगर पुलिस ने दबोच लिया। वहीं इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर सोमवार रात करीब ढाई बजे जन्मदिन का जश्न मना रहे 10 युवकों को गिरफ्तार किया।

गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ हाईवे पर सोमवार रात हुड़दंग मचा रहे 13 आरोपितों को मोदीनगर पुलिस ने दबोच लिया। वहीं, इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर सोमवार रात करीब ढाई बजे जन्मदिन का जश्न मना रहे 10 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए बीच सड़कों पर हुड़दंग करने वालों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके वाहन भी सीज किए हैं।

दिल्ली-मेरठ हाईवे पर आरोपित स्कार्पियो कार का शीशा खोलकर गेट पर लटके हुए थे। तेज आवाज में गाने चल रहे थे। कार भी लापरवाही से चलाई जा रही थी। सूचना पर मोदीनगर पुलिस ने आरोपितों का पीछा करते हुए उन्हें राजचोपले पर पकड़ लिया। आरोपितों की दो स्कार्पियो कार पुलिस ने सीज कर दी है। आरोपितों की कार से शराब की बोतलें भी मिली हैं। एसीपी मोदीनगर रितेश त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र स्थित मोहल्ला खतरीवाडा के विनय, प्रदीप, सूरज, मनीष और सिकंदराबाद के डिप्टी, दीपक, राधेश्याम, दीपक कोहली, छोटू, प्रवीण सैनी, छोटू पंडित, जितेंद्र भाटी व नोएडा के सरफाबाद का लव कुमार है।

शादी में जाते वक्त मचा रहे थे हुड़दंग

आरोपित सोमवार रात अलग-अलग स्कार्पियो में सवार होकर शादी में जा रहे थे। इस बीच मोदीनगर में आते ही इन्होंने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। स्कार्पियो कार के शीशे खोलकर तेज आवाज में गाने बजाते हुए वाहनों को ओवरटेक कर रहे थे। कार के डिपर भी चालू थे। कुछ युवा तो शर्ट खोलकर शीशे पर लटक रहे थे।

लोगों ने वीडियो बनाकर दी सूचना

ऐसे में हादसा होने की संभावना बनी थी। पास से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने आरोपितों का पीछा करना शुरू कर दिया। राजचोपले के पास पुलिस ने इनकी कार रोक दी।

आधी रात में एलिवेटेड रोड पर जन्मदिन मनाने वाले 10 गिरफ्तार

पुलिस ने इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर सोमवार रात करीब ढाई बजे जन्मदिन का जश्न मना रहे 10 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ बलवा व शांति भंग की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। तीनों कारें सीज कर दीं। इससे साबित हुआ कि एलिवेटेड रोड पर हुड़दंग रोकने में लापरवाही बरतने वाले दो पुलिसकर्मियों के निलंबित होने बाद अन्य पुलिसकर्मी सतर्क हुए हैं। वहीं, इस रोड पर हुड़दंगियों पर लगाम कसने के लिए मंगलवार से चार पीसीआर तैनात कर दी गईं।

रात में कर रहे थे हुड़दंग

रात करीब ढाई बजे रेलवे पुल के ऊपर एलिवेटेड रोड पर 10 युवक तीन कार को खड़ी करके केक काट रहे थे। तेज ध्वनि में गाना बजाकर नाच रहे थे।

हुक्काबारों में धुआं हुई पुलिस की सख्ती, नियमों की लगातार उड़ रही धज्जियां

गाजियाबाद में नव वर्ष के जश्न में रेस्टोरेंटों और बार की आड़ में जमकर हुक्काबार चले। पुलिस की सख्ती और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उनमें देर रात तक ग्राहकों को हुक्का पिलाया गया। अधिक पैसे वसूले गए।

गाजियाबाद। नव वर्ष के जश्न में रेस्टोरेंटों और बार की आड़ में जमकर हुक्काबार चले। पुलिस की सख्ती और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उनमें देर रात तक ग्राहकों को हुक्का पिलाया गया। अधिक पैसे वसूले गए। पुलिस कार्रवाई और सोशल मीडिया पर हुक्काबार के वीडियो प्रसारित होने से इसकी पुष्टि हुई।

धुआं से गूंजा था कैसल कैफे

इंदिरापुरम कोतवाली पुलिस ने एक जनवरी की रात करीब 10 बजे कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर वसुंधरा सेक्टर-10 डी के मकान नंबर 135 में चलने वाले कैसल कैफे में छापा मारा। पुलिस के मुताबिक, अंदर चारों ओर धुआं ही धुआं था। काफी लोग हुक्का पी रहे थे। पुलिसकर्मियों को देखकर लोग धक्का-मुक्की करके भागने लगे।

पुलिस ने सात लोगों को पकड़ लिया है। उनकी पहचान पसौंड़ा के राज चौधरी, संजय कालोनी के आशू, सिहानी गेट के जतिन, राजेंद्र नगर सेक्टर-दो के मिथुन भूषण, मोहन मीकिंस सोसायटी वसुंधरा सेक्टर-पांच के कार्तिक सिंह, लाजपत नगर के नितिन शर्मा व पटेल नगर के आकाश प्रजापति के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि राज चौधरी कैफे की आड़ में हुक्काबार चला रहा था। पुलिस ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

पुलिस को चकमा देकर भाग गया मालिक

कौशांबी थाना पुलिस ने 30 दिसंबर को थाने के पास ही एंजल माल के द बंग बंग बार एंड रेस्टोरेंट में छापा मारा। चारों ओर धुआं फैला था। लोग हुक्का पी रहे थे। पुलिस को देखकर लोग भागने लगे। पुलिस ने नीलम विहार के सावन व अलीगढ़ के अरुण को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला का चंदन हुक्काबार का मालिक व रविंद्र संचालक है। दोनों मौके से भाग गए हैं।

पुलिस कठघरे में

द बंग बंग बार एंड रेस्टोरेंट कौशांबी थाना के पास में एंजल माल में चलता है। कैसल कैफे इंदिरापुरम कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर वसुंधरा सेक्टर-10 डी में चलता है। दोनों में पहले भी पुलिस ने छापामारी करके कार्रवाई की है। इनकी लगातार पुलिस अधिकारियों से शिकायत होती रहती है। कार्रवाई का इन पर असर नहीं पड़ता है। इससे लोग पुलिस को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं।

जमकर वसूले पैसे

इंटरनेट मीडिया पर हुक्काबार के दो वीडियो प्रसारित हुए हैं। दावा किया गया है कि दोनों वीडियो कौशांबी थाना क्षेत्र के एंजल माल में च ल ने वाले लिकर हाउस का एक जनवरी की रात का है। यह भी बताया गया है कि आमदिनों में भी यहां हुक्काबार चलता है। आमदिनों में एक हुक्का का 12 सौ रुपये वसूला जाता है। नव वर्ष पर दो से ढाई हजार रुपये तक वसूला गया।

रेस्टोरेंट, बार व कैफे की आड़ में चलने वाले हुक्काबारों को चिह्नित किया जा रहा है। कौशांबी व वसुंधरा में कार्रवाई भी हुई है। किसी भी कीमत पर क्षेत्र में हुक्काबार नहीं चलने दूंगी।

- डा. दीक्षा शर्मा, पुलिस उपायुक्त, ट्रांस हिंडन।

इन स्थानों पर चलते पाए जा चुके हैं हुक्काबार

- इंदिरापुरम कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर वसुंधरा सेक्टर-10डी।
- इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर-12, 13 व 15।
- कौशांबी थाना से चंद कदम की दूरी पर एंजल माल।
- इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के आदित्य माल।
- इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के न्याय खंड-तीन में शुक्र बाजार चौक।
- इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के न्याय खंड-दो में काला पत्थर।
- खोड़ा थाना क्षेत्र के वीरबल पुलिस चौके पास न्यू अजंता कालोनी।

राहुल का सुरक्षा घेरा टूटा, मुश्किल से पहुंचे

लोनी। सीलमपुर गोकुलपुरी से होकर लोनी पहुंची यात्रा में राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा मंच के पास आने तक टूट गया। सुरक्षा कर्मी बामुशकिल उन्हें मंच तक ले गए। इससे पहले प्रशासन ने राहुल के सुरक्षा कर्मियों से बात कर व्यवस्था बनाई थी लेकिन व्यवस्था को समर्थकों की भीड़ ने ध्वस्त कर दिया। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संबोधन के लिए एक मंच बनाया गया था। राहुल गांधी को मंच तक लाने की व्यवस्था पुलिस और प्रशासन ने की थी। पुलिस के जवान कार्यक्रम स्थल के बाहर गेट पर रस्सी पकड़े खड़े थे। करीब 12 बजे प्रियंका गांधी आई। प्रियंका गांधी मंच पर नहीं गई, वह राहुल का इंतजार करने लगी। करीब एक बजे राहुल गांधी यात्रा के साथ लोनी पहुंचे। राहुल के साथ उनके समर्थक भारी संख्या में थे। राहुल के चारों तरफ उनके सुरक्षा कर्मी थे लेकिन भीड़ के चलते राहुल गांधी फंस गए। किसी तरह वह कार्यक्रम स्थल के गेट तक पहुंचे। यहां उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें भीड़ से बचाकर मंच की ओर ले गए। वहां प्रियंका गांधी उनके साथ मंच पर गईं। संबोधन के बाद दोनों साथ ही मंच से ट्रॉनिका सिटी लोनी की तरफ चल पड़े।

चलता रहा कारवा जुड़ते रहे लोग

राहुल और प्रियंका गांधी पहली बार लोनी पहुंचे थे। दोनों को देखने के लिए लोग सुबह से ही अपने घरों से बाहर सड़कों पर आ गए थे। दोनों को देखने के लिए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आए थे। सभी अपने फोन में राहुल और प्रियंका को कैद कर रहे थे। दिल्ली-सहारनपुर मार्ग के इस सात किमी की यात्रा में लोग उन पर फूलों की वर्षा करते रहे। जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ रही थी, वैसे-वैसे लोग उनसे जुड़ते जा रहे थे। वह स्थानीय लोगों से भी मिलते हुए नजर आए। एक स्थान पर तो एक युवक के साथ वह तिरंगा फहराते नजर आए।

बॉटेनिकल गार्डन के पास दर्दनाक हादसा, यूटर्न से सड़क पार कर रही महिला को कार ने कुचला

सेक्टर-38ए स्थित बॉटेनिकल गार्डन के पास तेज रफ्तार कार ने मंगलवार को यूटर्न से सड़क पार कर रही एक महिला को कुचल दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सेक्टर-39 कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नोएडा। सेक्टर-38ए स्थित बॉटेनिकल गार्डन के पास तेज रफ्तार कार ने मंगलवार को यूटर्न से सड़क पार कर रही एक महिला को कुचल दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सेक्टर-39 कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक दिल्ली के गौतमपुरी की रीना कुमारी(40) मंगलवार को नोएडा में अपने रिश्तेदार के आई थीं। दोपहर करीब दो बजे बोटेनिकल गार्डन के पास यूटर्न से सड़क पार करने के दौरान एक तेज रफ्तार कार चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। कार की चपेट में आकर वह गंभीर से रूप से घायल हो गई।

सीसीटीवी में कैद हुआ घटना

उन्हें इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से सेक्टर-27 स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक की तलाश कर रही है। चालक का अबतक पता नहीं चल सका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

नहीं मिली कोई तहरीर

स्वजन ने मामले में अबतक कोई लिखित तहरीर नहीं दी है। गौरतलब है कि दैनिक जागरण ने बीते दिन शहर के प्रमुख चौराहों पर फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) नहीं होने के कारण अवैध कट व यूटर्न से सड़क पार करने की समस्या को उठाया था। जिसमें बोटेनिकल गार्डन के पास भी एफओबी नहीं होने की समस्या थी। बावजूद नोएडा ट्रैफिक पुलिस और नोएडा प्राधिकरण की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया।

एम्स का डॉक्टर बन पैर के ऑपरेशन के नाम पर दिव्यांग से 50 हजार ठगे, दी जान से मारने की धमकी

नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन के एक दिव्यांग से आरोपितों ने एम्स का डॉक्टर बनकर पैर के ऑपरेशन के नाम पर 50 हजार रुपये ठग लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने आरोपितों का विरोध किया तो अरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

गाजियाबाद। नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन के एक दिव्यांग से आरोपितों ने एम्स का डॉक्टर बनकर पैर के ऑपरेशन के नाम पर 50 हजार रुपये ठग लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने आरोपितों का विरोध किया तो अरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस पर पीड़ित ने आरोपित, उसके बेटे व साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजनगर एक्सटेंशन की आफिसर सिटी के अनुज मित्तल सब्जी विक्रेता हैं। उनका कहना है कि उनका वर्ष 2010 में ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में उनके पैर में गंभीर चोट आई थी और डाक्टरों ने पैर में राड डाली थी। हाल में ही उनकी मुलाकात मसूरी डासना के जाकिर से हुई।

फ्री में ऑपरेशन कराने का दिया झांसा

उन्होंने जाकिर से अपनी चोट के बारे में जिक्र किया और बताया कि पैर में अभी भी दर्द रहता है और डाक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा है। जाकिर ने कहा की उनके एक जानकार डॉक्टर राहत अली दिल्ली एम्स में है और वह उनका ऑपरेशन एम्स में फ्री करा सकते हैं। उनके सहमत होने पर जाकिर उन्हें लेकर दिल्ली राहत अली के पास पहुंचा। जहां राहत अली ने कहा कि ऑपरेशन में पांच से छह लाख रुपये का खर्चा आएगा, अगर वह 50 हजार रुपये उन्हें दे तो ऑपरेशन मुफ्त में हो जाएगा।

रुपये लेने के बाद संपर्क बंद किया

इसके बाद उन्होंने जाकिर और राहत अली को 50 हजार रुपये उधार लेकर दिए। इसके बाद आरोपितों ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया। वह राहत अली के पास दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि वह कोई डॉक्टर नहीं है और वह अपने बेटे मोहम्मद असलम के साथ मिलकर लोगों के साथ इस प्रकार की ठगी करता है। विरोध करने पर असलम ने उनके साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित का कहना है कि उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बाद में उन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। एसीपी नंदग्राम आलोक दुबे का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इनसाइड

देश की सबसे सुरक्षित डीजल कारों की लिस्ट, सेफ्टी को लेकर मिले हैं 5 स्टार

ग्लोबल एन कैप गाड़ियों की क्रैश टेस्ट करके उसकी सेफ्टी रेटिंग देता है जिससे यह तय होता है कि गाड़ी सड़क पर चलते समय कितनी सेफ है। आइये जानते हैं उन गाड़ियों के बारे में जिसे ग्लोबल एन कैप सबसे सुरक्षित गाड़ी मानती है।

नई दिल्ली। जब भी आप अपने परिवार के लिए नई कार खरीदने जाएं तो सबसे पहले सेफ्टी फीचर्स के बारे में जरूर पता करें। इस समय देश में एक से बढ़कर एक सेफ्टी फीचर्स से लैस गाड़ियां उपलब्ध हैं। अगर आप डीजल गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो नीचे बताई गई गाड़ियों के बारे में एक बार जरूर पढ़ें। इन्हें ग्लोबल एनकैप द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है।

1. Tata Nexon

टाटा नेक्सन को भारतीय बाजार में काफी पसंद किया जाता है। यही वजह है कि ग्लोबल एनकैप ने इसे क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में टाटा की एक अलग ही धाक है, वहीं सुरक्षा के मामलों में भी टाटा को टॉप पर रखा जाता है। अगर आप अपने परिवार के लिए टाटा की कार खरीदना चाहते हैं को टाटा नेक्सॉन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इस गाड़ी को एनकैप ने क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में 5 स्टार रेटिंग दिया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी हादसे के समय यह गाड़ी काफी हद तक आपको सेफ रख सकती है।

2. Tata Altroz

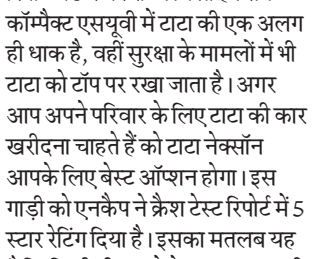

टाटा अल्ट्रोज भी भारत की सबसे सुरक्षित कारों की सूची में टॉप पर है। नेक्सॉन की तरह टाटा अल्ट्रोज को भी ग्लोबल एनकैप ने इसे 5 स्टार रेटिंग दी है। बेहद शानदार लुक के साथ आने वाली यह गाड़ी सेल्स के मामले में टाटा की बेस्ट कार है।

3.XUV 300

महिंद्रा XUV 300 को मजबूती के लिए जाना जाता है, इस एसयूवी को सेफ्टी के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है। Mahindra XUV300, GNCAP से 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली Mahindra की पहली सब-फोर-मीटर SUV है। अगर आप महिंद्रा की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इसे आप बेस्ट ऑप्शन मान सकते हैं।

4. Mahindra XUV700

ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली 5वीं भारतीय कार है। हालांकि, उपर बताई गई अन्य कारों की तुलना में इसकी कीमत अधिक है। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में अन्य कारों की तुलना में थोड़ी ज्यादा प्रीमियम है। इस गाड़ी की अधिक डिमांड होने के कारण इसका वेटिंग पीरियड भी काफी ज्यादा है।

5. Mahindra Marazzo

Mahindra Marazzo 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन द्वारा संचालित है, जो 120 bhp की पॉवर और 300 Nm की पीक टार्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। Marazzo में डुअल फ्रंट एयरबैग, सभी 4 डिस्क ब्रेक, ISOFIX माउंट, TCS, EBD के साथ ABS और कई अन्य सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं।

BMW ने X5 और X6 को किया ग्लोबली रिवील, जानिए इसमें क्या है खासियत

X5 और X6 दोनों में स्कल्पटेड बोनट बड़े किडनी ग्रिल और चौड़े एयर वेंट्स के साथ स्लीक एलईडी हेडलैंप हैं। बीएमडब्ल्यू का दावा है कि हेडलाइट्स पहले की तुलना में 35 मिमी एमएम नैरो हो गई हैं और एक्स5 में एक ऑप्शनल एलमुनिएटेंड फ्रंट ग्रिल मिलता है।

नई दिल्ली। जर्मन लक्जरी कार निर्माता BMW ने वैश्विक स्तर पर अपडेटेड BMW X5 और X6 को पेश कर दिया है। दोनों लग्जरी एसयूवी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में थोड़े बदलाव देखने को मिला है। इस कार कंपनी ने ऑनलाइन रिवील किया है। अप्रैल 2023 में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। हालांकि, इंडियन मार्केट में इस कार को कब पेश किया जाएगा इसके बारे में कंपनी ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है।

डिजाइन की बात करें तो X5 और X6 दोनों में स्कल्पटेड बोनट, बड़े किडनी ग्रिल और चौड़े एयर वेंट्स के साथ स्लीक एलईडी हेडलैंप हैं। बीएमडब्ल्यू का दावा है कि हेडलाइट्स पहले की तुलना में 35 मिमी एमएम नैरो हो गई हैं और एक्स5 में एक ऑप्शनल एलमुनिएटेंड फ्रंट ग्रिल मिलता है। X6 में स्टैंडर्ड एम स्पोर्ट पैकेज के साथ एक स्टैंडर्ड ऑक्टेनल लोवर फेस मिलता है। एसयूवी के पीछे रैप-अराउंड टेल लैंप और क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स दिए गए हैं। X5 के कलर ऑप्शन में ब्रुकलिन ग्रे, आइल ऑफ मैन ग्रीन और मरीना बे ब्लू शामिल हैं। X6 ब्लू रिज माउंटेन मेटैलिक, ब्रुकलिन ग्रे मेटैलिक, स्काईस्क्रेपर ग्रे मेटैलिक और फ्रोजन प्योर ग्रे मेटैलिक में उपलब्ध है। केबिन में बदलावों की बात करें तो इस लग्जरी कार में एक घूमने वाला डिजिटल पैनल है, डैशबोर्ड के ऊपर लगा है। बीएमडब्ल्यू के आईड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम में लेटेस्ट 8.0 वर्जन चल रहा है। इसमें स्टैंडर्ड रूप में 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और 14.9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलते हैं। इसमें बीएमडब्ल्यू लाइव कॉकपिट प्लस सिस्टम भी मिलता है, जिसमें क्लाउड-आधारित बीएमडब्ल्यू मैप्स नेविगेशन शामिल है।

सेकेंड हैंड लग्जरी कारों पर लोगों का बढ़ रहा भरोसा, साल 2022 में इन गाड़ियों की रही भारी डिमांड

यूज्ड कार मार्केट में सबसे ज्यादा लोग ऑडी क्यू3 मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास और बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज की डिमांड देखी गई वहीं जगुआर लैंड रोवर और वोल्वो जैसे अन्य लक्जरी ब्रांडों की बढ़ती मांग भी दर्ज की।

नई दिल्ली। भारत में लग्जरी कार चलाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं सेकेंड हैंड लग्जरी कार को पसंद करने वाली की संख्या भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सेकेंड हैंड कारों की बिक्री करने वाली कंपनी स्पिनी ने साल 2022 में बिकने वाली पुरानी लग्जरी कारों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लग्जरी यूज्ड कार मार्केट में 20 फीसद के करीब बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2022 औसतन 60,000 से अधिक सेकेंड हैंड लग्जरी कारों की बिक्री दर्ज की गई है।

गाड़ियों की तगड़ी डिमांड

यूज्ड कार मार्केट में सबसे ज्यादा लोग ऑडी क्यू3, मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास और बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज की डिमांड देखी गई, वहीं जगुआर लैंड रोवर और वोल्वो जैसे अन्य लक्जरी ब्रांडों की बढ़ती मांग भी दर्ज की। इसके अलावा कलर्स की बात करें तो व्हाइट, ग्रे और ब्लैक कलर इसी क्रम में उपभोक्ताओं की पहली पसंद बने हुए हैं। गुरूग्राम, दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में लक्ज़री कार के खरीददारों की संख्या सबसे अधिक रही है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद समझ में आता है कि लोगों का भरोसा यूज्ड लग्जरी कारों पर पहले से अधिक बढ़ता रहा है। इस साल 2023 में पिछले साल की तुलना में अधिक बिक्री की उम्मीद की जा रही है।

1.25 लाख रुपये कीमत और हीरो की ब्रांड वैल्यू... भारतीय बाजार में कितनी कामयाब होगी हीरो एक्सप्लस 200T 4V

Hero Xpulse 200T 4V भारतीय बाजार में Hero Xpulse 200T 4V लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने इसके लॉन्च के साथ अपने पोर्टफोलियो को अपडेट कर दिया है। आज हम आपको इससे जुड़ी खास बातों को बताने जा रहे हैं।

नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प लोगों के दिलों पर कई सालों से राज कर रही है। भारतीय बाजार में हीरो मोटोकॉर्प ने Hero Xpulse 200T 4V को अपडेट कर दिया है। यह मोटरसाइकिल Xpulse 200 सीरीज का रोड-बायस्ड वर्जन है और इस तरह यह ऑफ-रोड वेरिएंट की तुलना में अलग हार्डवेयर से भी लैस है। आज हम आपको इस मोटरसाइकिल की हाइलाइट्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

Hero Xpulse 200T 4V में सबसे बड़ा अपडेट वाल्व सेटअप के रूप में लाया गया है। पिछले मॉडल के विपरीत नई Xpulse 200T 4V दो-वाल्व लेआउट के बजाय चार-वाल्व सेटअप के साथ आती है। इसे पांच स्पीड के गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। ये मोटरसाइकिल 199.6cc, सिंगल-सिलेंडर, ऑयल/एयर-कूल्ड, चार-वाल्व मोटर 8,500rpm पर 18.8bhp का अधिकतम आउटपुट और 6,500rpm पर 17.35Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है।

कलर और डिजाइन

कलर और डिजाइन की बात करें तो इसमें कुछ चीजें सामान्य ही है। नई Xpulse 200T 4V में एलईडी हेडलाइट के ऊपर एक नई, बॉडी-कलर्ड फ्लाई स्क्रीन, बॉडी कलर्ड फ्रंट फेंडर और गेटर फ्रंट फोर्क्स हैं। वहीं पीछे की तरफ रियर टेल रैक को हटा दिया गया है। Xpulse 200T 4V में एक ट्यूबलर ग्रैब रेल है। इसी बीच इसके डिजाइन में स्कूप्ड सीट और साइड पैनल को पिछले मॉडल की तरह बरकरार रखा गया है। इसमें आपको तीन कलर ऑप्शन स्पोर्ट्स रेड, मैट फंक लाइम येलो और मैट शील्ड गोल्ड मिलते हैं।

फीचर्स के तौर पर इस मोटरसाइकिल में एक एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेललाइट, और कॉल अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन फंक्शन, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और एक साइड स्टैंड के साथ एक ब्लूटूथ-सक्षम एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है।

कीमत

नई Hero Xpulse 200T 4V एक वेरिएंट और तीन कलर ऑप्शन में आती है। पेट के सभी ऑप्शन 1,25,726 रुपये में उपलब्ध हैं। इसकी तुलना में दो-वाल्व वेरिएंट 1,24,396 रुपये में बेचा गया था।

सेना पर बेतुकी बयानबाजी रुकनी चाहिए

प्रताप सिंह पटियाल

यदि सैन्य अभियानों के सबूत चाहिए तो सैन्य भर्ती की मापदंड प्रक्रिया पूरी करके सेना का हिस्सा बनकर कड़े सैन्य प्रशिक्षण से गुजर कर सियासत व परिवार से कोसों दूर देश की सरहदों पर संगीनों के साए में वर्षों तक सैनिक का वास्तविक किरदार अदा करना होगा। सेना पर बेतुकी बयानबाजी बंद करनी होगी, सैन्य बलों के प्रति नजरिया सम्मानजनक हो'

'हमें अलग रहने दें' - यह शीर्षक भारतीय सेना के साबिक जनरल 'वेद प्रकाश मलिक' की पुस्तक 'कारगिल : एक अभूतपूर्व विजय' के एक अध्याय का है। सेना के शौर्य पर उठ रहे सवालों के मद्देनजर देश के लिए चार युद्धों में भाग ले चुके सेना के पूर्व जरनैल की 'हमें अलग रहने दें' वाली जज्बाती तहरीर सही साबित हो रही है। सन्-1999 की कारगिल जंग के दौरान वीपी मलिक भारतीय सेनाध्यक्ष थे। कारगिल की उसी शदीद जंग में भारतीय सेना ने अपने प्रचंड पराक्रम से 17 हजार फीट की बुलंदी पर मौजूद कारगिल के पहाड़ों पर घुसपैठ कर चुकी पाक फौज को अपनी कयामत की दुआ मांगने पर मजबूर कर दिया था। 29 अगस्त 1999 को कश्मीर में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हिमाचल के शूरवीर मेजर 'सुधीर वालिया' 'अशोक चक्र' (मरणोपरांत) कारगिल युद्ध के समय जरनल वीपी मलिक के एडीसी थे। लेकिन युद्ध के दौरान ही सुधीर वालिया ने तत्कालीन सेनाध्यक्ष से एक योद्धा की तरह कारगिल जंग के महाज पर जाने की अनुमति मांग कर अपने मोहिब्ब-ए-वतन के जज्बात जाहिर कर दिए थे। कारगिल में 25 जुलाई 1999 को 'जुलु टॉप' की भीषण जंग में पाक सेना की मंसूबाबंदी को नेस्तनाबूद करके वहां कब्जा करने में मेजर सुधीर वालिया ने अहम भूमिका निभाई थी। भावार्थ यह है कि सामरिक विषयों की अधूरी जानकारी के बिना सेना पर बेतुकी बयानबाजी करने वाले सियासतदानों को भारतीय सैन्य पराक्रम के स्वर्णिम इतिहास का अध्ययन करके हिंदोस्तान की सैन्य हशमत से रूबरू होने की जरूरत है।

यदि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था महफूज है तो इसके पीछे हमारी सशस्त्र सेनाओं की मुस्तैदी है। मजबूत लोकतंत्र शक्तिशाली सैन्य तंत्र पर निर्भर करता है। सेना किसी सियासी दल या मजहबी जमात के लिए नहीं लड़ती। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि सेना की संस्कृति है। सेना की मुस्तैदी से ही देश के नागरिक जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में भी सुरक्षित घूम रहे हैं। देश के तमाम इदारों पर हुक्मरानी करने वाले सियासी रहनुमाओं की सुरक्षा भी हमारे सशस्त्र बल ही सुनिश्चित करते हैं। 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने एलओसी के पार 'लक्षित हमले' को अंजाम देकर पीओके में मौजूद आंतकी लॉन्चपैड तबाह करके

कई आंतकियों को जहन्नुम की परवाह पर भेजकर उड़ी हमले का इंतकाम लिया था। 29 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के जंगी विमानों ने नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में स्थित आतंकी प्रशिक्षण शिवरों पर एयर स्ट्राइक करके सैकड़ों दहशतगर्दों का सफाया करके पुलवामा हमले में बलिदान हुए सीआरपीएफ के जवानों की शहादत का बदला लिया था। बालाकोट की एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को जकात में मिले पाक जंगी विमान एफ-16 को भी मार गिराया था। भारतीय सेना द्वारा पीओके में की गई स्ट्राइक के खौफ की लर्जिश पाक सेना से लेकर उनके हुक्मरानों के चेहरे पर आज भी झलकती है।

आतंक परस्त पाक के नामुराद हुक्मरान अमन के पैरोकार बनकर भारत से मुजाकरात को आमादा हो रहे हैं। भारत को एटम बमों से तबाह करने के ख्वाब देखने वाला पाकिस्तान खुद बर्बादी के मुहाने पर पहुंच चुका है। यदि पाक हुक्मरान अपने दिल-ए-नाशाद के साथ कई मुल्कों की कदमबोसी करके खैरात मांगने को मजबूर हैं तो यह भारत की कुशल सैन्य रणनीति व कूटनीति का परिणाम है। देश रक्षा में तैनात सशस्त्र सेनाओं तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के काम करने का ढंग अत्यंत गोपनीय तरीके से होता है। ज्ञात रहे युद्ध हो या कोई अन्य सैन्य ऑपरेशन, सेना केवल जीतने के लिए लड़ती है। जंग का नतीजा कभी भी दूसरे या तीसरे स्थान पर नहीं आता। जोखिम भरे सैन्य अभियानों की कीमत सैनिकों के परिवार चुकाते हैं। अतः सैन्य शौर्य पर सियासतदानों का बेवजह प्रलाप करना उन सैन्य परिवारों को आहत करता है जिनके सपूत देश के स्वाभिमान के लिए बलिदान हो चुके हैं। वोटों की फसल काटने या सियासी जमीन तराशने के लिए देश के समक्ष बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर आम लोगों के हितों की पैरवी होनी चाहिए। 26 जनवरी 2023 को राजधानी दिल्ली के 'कत्र्तव्य पथ' पर 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सैन्यशक्ति संपन्न हिंदोस्तान ने दुश्मन के होश फाख्ता करने वाले हथियारों की नुमाईश के जरिए दुनिया को अपनी सैन्य कूवत का पैगाम देकर बता दिया कि विश्व की चौथी शक्तिशाली भारतीय सेना राष्ट्र की हिफाजत के लिए अपने इस विध्वंसक जखीरे की आजमाईश करने में गुरेज नहीं करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध व राष्ट्रवाद की प्रबल प्रतीक भारतीय सेना को रणभूमि में शत्रु के समक्ष शौर्य पराक्रम की दास्तान-ए-शुजात का हुनर विरासत में मिला है।

यही कारण है कि दहशतगर्दी के मरकज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ हर साजिश सरहद पर ही दम तोड़ रही है। कश्मीर में आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। चूंकि भारतीय सेना का आक्रामक मिजाज व लहजा दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखाने वाला रहा है। अपनी फितरत कभी भी जाहिर नहीं करने वाला शातिर ड्रैगन भी हिंदोस्तान की सैन्य ताकत के जोशीले अंदाज के आगे बेबस नजर आ रहा है। सशस्त्र सेनाओं की कार्यशैली युवाओं के लिए आदर्श व आकर्षक है। इसीलिए देश के करोड़ों युवा सैन्य वर्दी पहनने की हसरत रखते हैं। अतः पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क की सरजमीं पर सफलतम सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने वाली विश्व की सर्वोत्तम भारतीय थलसेना के अदम्य साहस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। लाजिमी है सैन्यबलों के प्रति नज़रिया सम्मानजनक हो ताकि दुश्मन की हर हिमाकत को सरहद पर ही खल्लास करने वाली हिंद की सैन्य सलाहियत का इकबाल बुलंद रहे। लेकिन यदि सैन्य अभियानों के सबूत चाहिए तो सैन्य भर्ती की मापदंड प्रक्रिया पूरी करके सेना का हिस्सा बनकर कड़े सैन्य प्रशिक्षण से गुजर कर सियासत व परिवार से कोसों दूर देश की सरहदों पर संगीनों के साए में वर्षों तक सैनिक का वास्तविक किरदार अदा करना होगा।

संपादक की कलम से

खेल मानचित्र के लिए

खेल नीति के बड़े दरवाजों के नीचे कहीं स्कूली या ग्रामीण खेलें दब न जाएं। कहां तो जयराम सरकार ने भी एक 'खेल नीति' बनाई थी और कहां आज फिर हिमाचल को चाहिए एक नई नवेली 'खेल नीति'। पिछले कुछ सालों से प्रदेश में कम से कम 'खेल नीति' पर विचार-विमर्श तो शुरू हुआ है, वरना यह मंत्रालय गौण था। अब तेज-तर्रार व युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने दायित्व में खेल वातावरण की सघन खोज में हरियाणा की नीति से ऐसा कुछ हासिल करना चाहते हैं ताकि समग्रता से कुछ किया जा सके। वैसे पिछली सरकार के खेल मंत्री रहे राकेश पठानिया ने भी 'खेल नीति' के तहत कई लारे-लप्पे लगाए, लेकिन नूरपुर स्टेडियम के अलावा उनके कार्यकाल ने अन्य कोई इबारत नहीं लिखी। कुछ यही रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से प्रदेश की अभिलाषा का भी रहा है, जहां सारी योजनाएं-परियोजनाएं धरी की धरी रह गईं। हालांकि इस बार केंद्रीय खेल बजट में करीब तीन सौ पैंतीस करोड़ का इजाफा हुआ है, लेकिन भारतीय खेल प्राधिकरण को पिछले वर्ष से 132 करोड़ अधिक मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त खेलो इंडिया खेलो को हजार करोड़ तथा खेल संघों को 325 करोड़ मिल रहे हैं।

मणिपुर के खेल विश्वविद्यालय को पिछले साल के 91 करोड़ के मुकाबले 107 करोड़ की राशि आवंटित हो रही है। जाहिर है पिछली राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के कई प्रस्ताव धूल चाटते मिल जाएंगे, तो अब नए सिरे से खेलों की प्रस्तावना और योजनाओं का खाका बनेगा। हिमाचल न केवल हरियाणा, बल्कि कई अन्य राज्यों और खास तौर पर मणिपुर से बहुत कुछ सीख सकता है, बशर्ते सारे प्रयास खिलाडियों की खोज से शुरू होकर उनके खेल भविष्य को सुनिश्चित करें। पहले ही हिमाचल सरकार ने खेल स्कूलों व खेल महाविद्यालयों की शुरुआत करने की घोषणा कर रखी है और अगर इस तरह खेल करिअर को बुनियादी सहूलियतें, प्रशिक्षण तथा आगे बढऩे की गारंटी मिले, तो खेल वातावरण सुदृढ़ होगा। हिमाचल को सर्वप्रथम खेल संघों के सजावटी नेतृत्व से निजात चाहिए और कुछ खेलों पर केंद्रित होकर लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। क्रिकेट एसोसिएशन ने खिलाडियों के चयन से प्रशिक्षण तक जिस व्यवसायीकरण को तराशा, उसके नतीजे सामने हैं। हिमाचल के क्रिकेट खिलाड़ी आज राष्ट्रीय टीमों में स्थान बना रहे हैं, तो यह योगदान महिला एवं पुरुष क्रिकेट अकादमियों का है। साई के दो छात्रावासों के माध्यम से कुछ खेलों में हिमाचली प्रतिभा आगे बढ़ी है, लेकिन न तो हाई आल्टीट्यूट प्रशिक्षण केंद्र बना और न ही पूरे प्रदेश में विभिन्न खेलों के उचित प्रशिक्षण को स्थान मिला। एक गंभीर कोशिश तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के दौर में हुई जब एक साथ कई निपुण कोच नियुक्त किए गए तथा सिंथैटिक ट्रैक तथा एस्ट्रोटर्फ बिछाने की पहल हुई।

बेशक इस बीच कुछ इंडोर स्टेडियम भी तैयार हुए या स्वीमिंग के लिए अधोसंरचना पर काम हुआ, लेकिन समग्रता से राज्य का खेल मानचित्र अभी तक तैयार नहीं हुआ। हमारा मानना है कि खेलों में क्रांति लाने के लिए टैलेंट हंट की जरूरत है और इसके लिए हरियाणा, पंजाब, मणिपुर, कर्नाटक व महाराष्ट्र के आदर्श हमारे सामने हैं। दूसरी ओर ग्रामीण व स्कूली खेलों के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं के निरंतर आयोजन की व्यवस्था करनी होगी, जबकि अधोसंरचना निर्माण व विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण के लिए निजी अकादमियों को प्रोत्साहित करना होगा। हिमाचल को अगर राष्ट्रीय खेलों के मानचित्र में प्रवेश करना है, तो एक बार राष्ट्रीय खेल आयोजित करने होंगे। राष्ट्रीय खेल आयोजन से कम से कम दस जिलों का खेल ढांचा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण, सुविधाओं व आयोजन के काबिल हो जाएगा। मसलन राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ अगर धर्मशाला में होता है, तो एक स्टेडियम के अलावा कितने ही अन्य ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, नाहन, सोलन, शिमला, कुल्लू व चंबा तक स्थापित हो जाएंगे।

09 फरवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लियो कार्टर ने एक ओवर में छः छक्के लगाए। यह कीर्तिमान बनाकर विश्व के सातवें बल्लेबाज के रूप में उन्होंने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। कार्टर के अलावा अब तक वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स, भारत के रवि शास्त्री और युवराज सिंह, दक्षिण अफ्रीका के हर्शल गिब्स, इंग्लैंड के रॉस विटाली और अफ़ग़ानिस्तान के हजरतुल्ला ज़ज़ई ने एक ओवर में छः छक्के लगाये हैं।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने 457 .468 बिलियन के उच्च स्तर को छुआ।

2014 – भारतीय संचार उपग्रह जीसैट-14 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। जीसैट -14 में भारत में निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ था।

2010 – 'हरित राजस्थान अभियान' के तहत डूंगरपुर ज़िला प्रशासन द्वारा ज़िले भर में फैली बंजर पहाड़ियों की हरितिमा लौटाने के लिए 11 अगस्त व 12 अगस्त, 2009 को किए गए 6 लाख से अधिक पौधारोपण की मुहिम को 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में सम्मिलित कर लिया गया।

2009 – नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

2008 – यूरोपीय संघ (ईयू) ने पाकिस्तान में चुनाव पर्यवेक्षण अभियान पूर्णरूप से शुरू किया।

उत्तर प्रदेश में वैट अध्यादेश लागू होने के आद 'उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट', 1948 समाप्त। 'भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड' (सेल) के 'लौह एवं स्टील अनुसंथान एवं विकास केन्द्र' को वर्ष 2008 का 'गोल्डन पीकाक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सर्विस पुरस्कार' के लिए चुना गया। पाकिस्तान के सूबा-ए-सरहद प्रान्त के गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। यूरोपीय संघ (ईयू) ने पाकिस्तान में चुनाव पर्यवेक्षण अभियान पूर्णरूप से शुरू किया।

2007 – तंजानिया की विदेश मंत्री आशा रोज मिगरो संयुक्त राष्ट्र की उपमहासचिव नियुक्त।

2006 – भारत और नेपाल ने पारगमन संधि की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाया।

2003 – अल्जीरिया में विद्रोहियों के हमले में 43 सैनिक मरे।

2002 – दक्षेस शिखर सम्मेलन काठमाण्डू में शुरू, उद्घाटन सत्र में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया पर भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा- 'भरोसे के लायक़ नहीं।'

2000 – अंतर्राष्ट्रीय फ़ुटबाल एवं सांख्यिकी महासंघ ने 'पेले' को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया।

1999 – विक्टर जॉय वे पेरू के प्रधानमंत्री मनोनीत किये गए, आस्ट्रेलिया के कप्तान मार्क टेलर द्वारा 157 कैच पकड़कर विश्व रिकार्ड की स्थापना।

हजारों मौतों का जलजला

तुर्किए और सीरिया में ऐसा जलजला आया कि अल सुबह की घड़ी में जो नींद में डूबे थे, वे हमेशा के लिए ही सो गए। धरती कांपी और कांपती रही। खौफ और मौत की दहशत के वे लम्हे कैसे रहे होंगे? भोर में 4.17 बजे भूकंप की तीव्रता 7.8 थी, जो सब कुछ लील गई। घर, मकान, भवन, स्मारक, अट्टालिकाएं, पेड़, बिजली के खंभे, गैस पाइपलाइन और हवाई अड्डे का रन-वे आदि, देखते ही देखते, ज़मींदोज हो गए। तुर्किए के 10 बड़े शहर 'मलबा' हो गए। जो बसेरे थे, वे खंडहर हो गए। मंगलवार सुबह तक जलजले ने 4365 ज़िंदगियां छीन ली थीं और 15,000 से ज्यादा घायल बताए गए थे। तुर्किए की 3470 से ज्यादा इमारतें ज़मींदोज हो चुकी हैं। जो ज़िंदा बचे हैं, उनके लिए बरबस ही 'भगवान' याद आते हैं-'जिसको राखे साइयां, मार सके ना कोय।' जलजला एकबारगी नहीं था। तीन बार धरती भयावह रूप से कांपी। अलबत्ता सोमवार की शाम तक तुर्किए और सीरिया के लोग 78 झटके महसूस कर चुके थे। तबाही और बर्बादी के बाद भी मंगलवार को भूकंप का कंपन महसूस किया गया। इन जलजलों ने तुर्किए को एक देश के तौर पर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि तुर्किए गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुज़र रहा है। वहां की मुद्रा का बेहद अवमूल्यन हो चुका है। देश पर भारी कजऱ् है। आम चुनाव 14 मई को होने थे, लेकिन विनाश के ऐसे दौर में उन्हें स्थगित किया जा सकता है। इस समय तुर्किए में बर्फीली और कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। तापमान शून्य से भी नीचे है। ऐसे दौर में लोग बेघर और बर्बाद हुए हैं। उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? बीते 3 सालों के दौरान यह तीसरा बड़ा भूकंप है और 24 सालों के दौरान वहां हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं। विशेषज्ञ 100 सालों के दौरान इसे सबसे भयानक और तीव्र भूकंप मान रहे हैं। इसे 1939 के जलजले की पुनरावृत्ति भी माना जा रहा है, क्योंकि तब भी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.8 मापी गई थी। उसमें 30,000 से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई थीं। वर्ष 1999 वाले भूकंप में भी करीब 18,000 लोग मारे गए थे, लिहाजा आशंका है कि मौत का आंकड़ा 'अकल्पनीय' स्तर तक बढ़ सकता है। बेशक तुर्किए सबसे खतरनाक भूकंप संवेदी देशों में गिना जाता है। वहां ऐसे जलजलों का इतिहास रहा है, लेकिन वह दुनिया के खूबसूरत देशों में भी शामिल है। यह अजीब विरोधाभास है। कुदरत ने एक ही झटके में तुर्किए को ध्वस्त कर बदरूप बना दिया। 'मलबे का ढेर' बना दिया। कितना बौना और असहाय है मनुष्य! वह चांद, मंगल ग्रह तक पहुंच सकता है, लेकिन ज़मीन के भीतर की करवटों और टकराहटों से नहीं जीत पाया है। इन जलजलों ने तुर्किए, सीरिया को ही तबाह नहीं किया, बल्कि लेबनान, साइप्रस, इराक, यूनान, डेनमार्क, इजऱायल और फलस्तीन आदि देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहां के जान-माल के नुकसान के ब्योरे प्रतीक्षित हैं। तुर्किए में आपातकाल और राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। बहरहाल ये तो सरकारी औपचारिकताएं हैं, लेकिन गंभीर चुनौती यह है कि अब ज़िंदगियां बचाने की जंग कैसे लड़ी जाएगी। सकारात्मक है कि अमरीका, यूरोपीय देशों से लेकर भारत तक ने सहयोग और मदद के हाथ बढ़ाए हैं। भारत ने एनडीआरएफ की 100 सदस्यीय टीमों के साथ डॉग दस्ता, मेडिकल टीम और जरूरी दवाएं भेजी हैं।

Haldwani Protest के स्वरूप ने साबित किया- 'शाहीन बाग' संयोग नहीं प्रयोग था जोकि दोहराया जा रहा है

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी में बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए ढांचों को गिराने के आदेश दिए थे। न्यायालय ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स की मदद ले।

अवैध कॉलोनियों से जब भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है तो उसे सियासी लोग धार्मिक रंग देने का काम करते हैं। दिल्ली में पिछले साल एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग समेत कई अन्य इलाकों में पहुँचा तो इस कार्रवाई को एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ अभियान करार दिया गया। अब उत्तराखंड चर्चा में है क्योंकि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी से कब्जा हटाने का जो आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया है उसके खिलाफ सियासत शुरू हो गयी है। एकदम शाहीन बाग के आंदोलन की तर्ज पर महिलाओं और बच्चों को ठंड के मौसम में आगे कर प्रदर्शन करवाया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। यहाँ हमें समझना होगा कि सरकारी जमीन सार्वजनिक संपत्ति होती है किसी एक की बपौती नहीं। सरकारी जमीन से कब्जा छुड़वाने के प्रयास को अन्याय का रूप देना गलत है। देश संविधान से चलता है ना कि भावनात्मक या धार्मिक आधार पर। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है तो नेताओं को बड़बोले बयान देने की बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए। वैसे हल्द्वानी में आंदोलन का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है उससे एक बात साबित हो गयी है कि शाहीन बाग कोई संयोग नहीं बल्कि प्रयोग था जोकि अब जगह-जगह दोहराया जा रहा है।

जहां तक हल्द्वानी मामले की बात है तो आपको बता दें कि अवैध कॉलोनी बताये जा रहे बनभूलपुरा के पांच हजार से ज्यादा घरों पर संकट मंडराने लगा है क्योंकि रेलवे ने अपनी जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए जो याचिका दायर की थी उस पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जमीन खाली कराने के निर्देश दिये हैं। इसके बाद सियासत ऐसी शुरू हो गयी है कि इस पहाड़ी राज्य के नेताओं से लेकर हैदराबाद के ओवैसी तक इस मामले में कूद गये हैं। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच चुका है और पांच जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका स्थानीय निवासियों के साथ हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक ने दाखिल की है। उनके वकील सलमान खुर्शीद हैं। दूसरी याचिका वकील प्रशांत भूषण ने दाखिल की है। रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा सुनवाई करेंगे।

हम आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी में बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए ढांचों को गिराने के आदेश दिए थे। न्यायालय ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स की मदद ले, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाए। इसके बाद जगह खाली करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों की मदद से नोटिस दिये गये। जिसके बाद हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में क्षेत्र के निवासियों ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इलाके के लोगों का कहना है कि वे लोग इस क्षेत्र में 70 साल से रह रहे हैं। वहां 20 मस्जिदें, 9 मंदिर, पानी की टंकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1970 में डाली गई एक सीवर लाइन, दो इंटर कॉलेज और एक प्राथमिक विद्यालय है इसलिए यह क्षेत्र अवैध कब्जे वाला नहीं है। इलाके के लोगों का कहना है कि हम प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वे इस तथा-कथित अतिक्रमण को हटाने पर मानवीय पहलू से विचार करें। इलाके के लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर यह रेलवे की जमीन थी तो सरकार ने इसे पट्टे पर कैसे दिया था? इस मामले में क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा, "करीब सौ साल से इस क्षेत्र में लोग बसे हुए हैं। यहां 70 साल पुरानी मस्जिदें और मंदिर हैं। यहां नजूल जमीन, पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और लीजधारक हैं।" उन्होंने कहा, "रेलवे जिस 78 एकड़ जमीन को अपना बताता है, उसे खाली करने का विरोध करने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय गये। हम उच्चतम न्यायालय भी गये जहां हमारे वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद मामले की पैरवी कर रहे हैं लेकिन जिस सरकार ने जमीन पर स्कूल एवं अस्पताल बनवाये, उसने अपने नागरिकों की कोई परवाह नहीं की।"

स्कूली शिक्षा के लिए संघर्ष

डा. वरिंदर भाटिया

स्कूली शिक्षा देश के सभी बच्चों को आसानी से मिले, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। पैसे की कमी के कारण गरीब के बेटे और बेटी के लिए गुणात्मक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में रुकावट नहीं बननी चाहिए। माननीय हाई कोर्ट का फैसला प्रशंसनीय है क्योंकि इसमें फीस न दे पाने पर छात्र की पीड़ा पर मरहम लगाई गई है। गरीब छात्रों को निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए' दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शिक्षा के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण अधिकार है और फीस का भुगतान न कर पाने के कारण किसी छात्र को क्लास में बैठने या मिड-सेशन के एग्जाम देने से रोकना गलत है। माननीय अदालत ने यह निर्देश दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल के 10वीं क्लास के एक छात्र की याचिका के संदर्भ में दिया है। इस केस में छात्र का नाम फीस न देने के कारण स्कूल से हटा दिया गया था। छात्र ने कोर्ट में याचिका डालकर आगामी बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने की मांग की थी। शिक्षा का अधिकार कानूनी तौर पर एक मौलिक और मूल अधिकार होने के बावजूद आज भी हमारे अनेक गरीब छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। विदित हो कि भारत की संसद द्वारा अगस्त 2009 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर सहमति की मुहर लगाई गई थी और 1 अप्रैल 2010 से यह कानून पूरे देश में लागू हुआ।

इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों की कानूनी रूप से यह बाध्यता हो गई कि वे 6 से 14 साल आयु समूह के भारत के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। आजादी के 62 वर्षों बाद पहली बार एक ऐसा कानून बना था जिससे 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार हासिल हो सका। निश्चित रूप से इस कानून की अपनी सीमाएं रही हैं, जैसे 6 वर्ष से कम और 14 वर्ष से अधिक आयु समूह के बच्चों को इस कानून के दायरे से बाहर रखना, शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त जोर नहीं देना, इस कानून के पीछे की मंशा और और पिछले दस वर्षों के दौरान जिस तरह से इसे अमल में लाया गया है, उसमें काफी फर्क है। क्या यह जरूरी नहीं कि शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए, जो महज आंकड़ों के मकडज़ाल से आगे बढ़ते हुए शिक्षा का अधिकार कानून के बुनियादी सिद्धांतों पर केन्द्रित हो। कहना न होगा कि एक दशक बाद शिक्षा का अधिकार कानून की उपलब्धियां सीमित हैं। इस कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार लोग पिछले अनेक सालों के दौरान इससे अपना पीछा छुड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या पिछले दस वर्षों के दौरान केंद्र और राज्य सरकारें आरटीई को लागू करने में उदासीन रही हैं? इस बात के गवाह रहे हैं कि छात्र किस तरह से भारत की स्कूली शिक्षा की अधोसंरचना, पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उपेक्षा से जूझता रहे हैं। इस बात का विश्लेषण किया जाए कि पिछले कई वर्षों के दौरान आरटीई स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में क्यों विफल साबित हुआ है। आज प्राथमिक स्कूलों में नामांकन तो हो गए हैं लेकिन स्कूलों में बच्चों के टिके रहने की चुनौती अभी भी बरकरार है। इसी के साथ ही आज भी बड़े पैमाने पर अनेक राज्यों में सरकारी स्कूल बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, जरूरी संसाधन, शिक्षा के लिए माहौल और शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। सार्वजनिक शिक्षा एक आधुनिक विचार है जिसमें सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, वर्ग, भाषा आदि के हों, शिक्षा उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। गौरतलब है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां सदियों तक शिक्षा पर कुछ खास का एकाधिकार रहा है। यह सिलसिला औपनिवेशिक काल में टूटा, जब भारत में स्कूलों के माध्यम से सबके लिए शिक्षा का प्रबंध किया गया। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा स्थापित स्कूल-कालेज सभी भारतीयों के लिए खुले थे। अंग्रेजों द्वारा स्पष्ट नीति अपनाई गई कि जाति और समुदाय के आधार पर किसी भी बच्चे को इन स्कूलों में प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव था जिसने सभी भारतीयों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोल दिया। आजादी के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में भारत के सभी नागरिकों को धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के किसी भेदभाव के बिना किसी भी शिक्षा संस्थान में भर्ती होने का अधिकार दिया गया। वैसे शिक्षा का अधिकार कानून की कुछ खूबियां भी हैं। साल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून के लागू होने के बाद पहली बार केंद्र और राज्य सरकारों की कानूनी जवाबदेही बनी कि वे 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही इस कानून की सबसे बड़ी सीमा यह रही है कि इसने सार्वजनिक और निजी स्कूलों के अंतर्विरोध से कोई छेड़छाड़ नहीं की। शिक्षा का अधिकार कानून ने न केवल शिक्षा की दोहरी व्यवस्था को बनाए रखा है बल्कि इसे मजबूत बनाने में भी मददगार साबित हुआ है। इसने सरकारी स्कूलों को 'मजबूरी की शाला' में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो लोग सक्षम हैं उनकी दौड़ पहले से ही प्राइवेट स्कूलों की तरफ है। इस स्थिति को हमें बदलना होगा। बहरहाल पिछले तीन दशकों के दौरान दुनिया बहुत तेजी से बदली भी है और इसी के साथ ही देश-दुनिया की शिक्षा प्रणाली बढ़ती जरूरतों और मांगों के अनुसार कई बदलावों से गुजरी है।

इनसाइड

इंडिगो विमान कोलकाता में लैंडिंग के दौरान क्षतिग्रस्त; प्लेन को ग्राउंडेड किया गया, जांच जारी

नई दिल्ली। नागर विमानन कंपनी इंडिगो ने कहा है कि दो जनवरी 2023 को A321 VT-ILR पर चलने वाली उड़ान 6E 114 की कोलकाता में लैंडिंग के दौरान टेल से कुछ टकरा गया है। मूल्यांकन और मरम्मत के लिए विमान को कोलकाता में ग्राउंडेड घोषित कर दिया गया है। घटना की विस्तृत जांच की जा रही है।

फेड के फैसले पर बाजार की नजर, सेंसेक्स-निफ्टी में सपाट ढंग से शुरू हुआ कारोबार

नई दिल्ली। बुधवार के कारोबारी सेशन में सेंसेक्स 61294 पर और निफ्टी 18230 अंकों के लेवल पर खुला। फेड के फैसले से पहले शुरुआती कारोबार में बाजार पर दबाव दिख रहा है। सेंसेक्स में 75 अंकों से अधिक की गिरावट आ गई है। दबाव के बावजूद इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, सनफार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और SBI, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स में मजबूती है। वहीं दूसरी ओर टाटा स्टील, पावरग्रिड, इन्फोसिस और टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में कमजोरी दिख रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की मजबूती के साथ 82.84 के स्तर पर खुला। बुधवार को बाजार के शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में डीमार्ट के शेयरों में 2% की गिरावट जबकि इंडसइंड के शेयरों में बढ़त दिख रही है। इससे पहले वैश्विक बाजार में डाओ जोन्स में 11 अंकों की मामूली कमजोरी दर्ज दिखी। एसएंडपी 500 में 0.40 फीसदी और टेक कंपनियों आधारित इंडेक्स Nasdaq में 0.76 फीसदी की गिरावट देखी गई। इस दौरान बाजार की नजर फेडरल रिजर्व की तरफ से जारी होने वाली मिनट्स पर बनी रही। उससे पहले निवेशक असमंजस में नजर आ रहे हैं। 2022 में अमेरिकी बाजार का प्रदर्शन 2008 के बाद सबसे कमजोर रहा। इसका सबसे बड़ा कारण फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी ही है। डॉलर इंडेक्स 104.36 पर है। क्रूड के भाव में चार फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और यह 82 डॉलर प्रति बैरल के नीचे लुढ़क गया।

बैंक घोटालों में RBI कर्मियों की संलिप्तता के दावे झूठे, केंद्रीय बैंक ने दाखिल किया हलफनामा

एनटीवी न्यूज

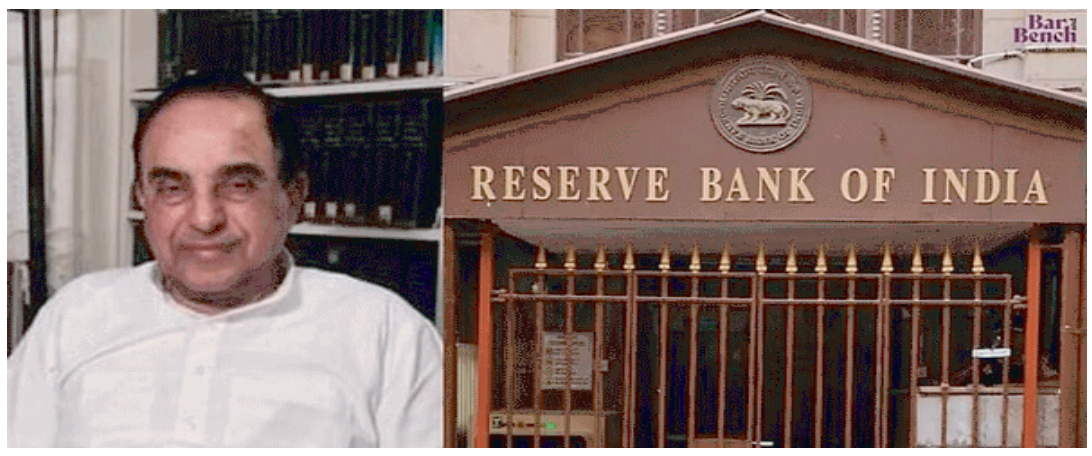

नई दिल्ली। आरबीआई ने शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में कहा, "इस संबंध में, यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता की ओर से घोटालों को आरबीआई अधिकारियों से जोड़ने की कोशिश करने वाले दावे याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए किसी भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अभाव में भ्रामक हैं और इसकी पुष्टि नहीं हुई है।"

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से विभिन्न बैंकिंग घोटालों में उसके अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच की मांग वाली याचिका में जो बातें हैं वे "भ्रामक और गैर-प्रमाणित" हैं।

आरबीआई ने न्यायालय से यह भी कहा कि उसके पास कर्मचारियों के आचरण की जांच के लिए आंतरिक तंत्र मौजूद है। स्वामी की याचिका खारिज करने की मांग करते हुए आरबीआई ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है और यह तथ्यात्मक तथा कानूनी त्रुटियों से पूर्ण है।

आरबीआई ने शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में कहा, "इस संबंध में, यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता की ओर से घोटालों को आरबीआई अधिकारियों से जोड़ने की कोशिश करने वाले दावे याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए किसी भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अभाव में भ्रामक हैं और इसकी पुष्टि नहीं हुई है।"

इसमें कहा गया, "यह अनुरोध किया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप है, या उसके कार्यों या चूक के संबंध में प्रथम दृष्टया सबूत हैं तो उसके आचरण की जांच करने के लिए आरबीआई के पास एक आंतरिक तंत्र/ढांचा है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई सबूत या विशिष्ट आरोप प्रस्तुत नहीं किया है और प्रतिवादी संस्था के खिलाफ केवल अस्पष्ट और भ्रामक आरोप लगाए गए हैं।"

आरबीआई ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसका एक केंद्रीय सतर्कता प्रकोष्ठ (सीवीसी) भी है, जो कर्मचारियों के आचरण की निगरानी करता है। विभिन्न बैंकिंग घोटालों में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच की मांग करने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के जवाब में केंद्रीय बैंक की ओर से यह हलफनामा दायर किया गया।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान स्वामी को हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। न्यायालय ने 17 अक्टूबर को स्वामी की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आरबीआई को नोटिस जारी किये थे।

स्वामी ने आरोप लगाया है कि किंगफिशर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यस बैंक जैसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े घोटालों में आरबीआई अधिकारियों के शामिल होने की जांच नहीं की गई। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरबीआई के अधिकारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हुए 'सक्रिय रूप से मिलीभगत' की।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें अहमदाबाद के अतिरिक्त आयकर आयुक्त संतोष करनानी को अग्रिम जमानत देने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। करनानी को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। इसके बाद पीठ ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौते से दोनों देशों को लाभ, दो वर्षों में बढ़ेगा 100% रोजगार

नई दिल्ली। मुक्त व्यापार समझौते से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले छात्रों और पेशेवरों के लिए भी अवसर बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में निवेशकों और महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाली टेक कंपनियों के लिए काम करने वालों को चार साल तक का वीजा मिलेगा। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फारेल एओ ने कहा है कि मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। इसे विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इस व्यापार समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले 96% भारतीय सामानों पर शुल्क को कम कर दिया गया है। इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में रोजगार सृजन होगा। इसमें अगले दो वर्षों में रोजगार में 100% तक वृद्धि होगी। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फारेल एओ के अनुसार मुक्त व्यापार समझौते से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले छात्रों और पेशेवरों के लिए भी अवसर बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में निवेशकों और महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाली टेक कंपनियों के लिए काम करने वालों को चार साल तक का वीजा मिलेगा। उन्होंने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया में योग्य शेफ और योग शिक्षकों के लिए ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते महत्व को देखते हुए उनसे जुड़ी नौकरियों के लिए भी एक वर्ष में 1800 वीजा जारी किए जाएंगे।'

देश में ही बनेंगे मानवरहित विमानों के कलपुर्जे, जनरल एटॉमिक्स ने भारत फोर्ज से किया करार

एनटीवी न्यूज

नई दिल्ली। अमेरिका की शीर्ष ड्रोन निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने भारत में मानवरहित विमानों के लैंडिंग उपकरणों और कलपुर्जों के निर्माण के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ करार की घोषणा की है।

इस कदम से भारत में अत्याधुनिक ड्रोन के निर्माण के लिए एक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में मदद मिलेगी।

जनरल एटॉमिक्स की एक सब्सिडियरी इकाई सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम (जीए-एएसआई) ने कहा है कि भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ उसकी साझेदारी दोनों कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण में सहायक होगी। इससे भारत में मानवरहित विमान उद्योग को गति मिलेगी।

जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी विवेक लाल ने कहा, "जीए-एएसआई मानवरहित विमानों के कलपुर्जों के निर्माण के लिए भारत फोर्ज के साथ काम करने को लेकर उत्सुक है।"

कंपनी ने कहा है कि उच्च-प्रदर्शन वाले महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण में पांच दशकों से अधिक के अनुभव के साथ भारत फोर्ज उत्पादों की अवधारणा, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, निर्माण, परीक्षण और सत्यापन की क्षमता रखता है।

भारत फोर्ज लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बाबा कल्याणी ने कहा कि एयरोस्पेस एक 'गहन प्रौद्योगिकी' क्षेत्र है, जो उत्पाद की शुद्धता, विश्वसनीयता और उसके दोषरहित होने पर निर्भर करता है।' उन्होंने कहा, अपनी एयरोस्पेस विकास रणनीति के तहत हमने जीए-एएसआई के साथ साझेदारी की है।

गूगल 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10% जमा कराए, एनसीएलएटी ने दिए निर्देश

नई दिल्ली। NCLAT ने गूगल की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे जुर्माने का 10% जमा करने को कहा। इस बीच ट्रिब्यूनल ने गूगल पर सीसीआई के दंड आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

एनसीएलएटी ने गूगल को सीसीआई की ओर से लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में कथित उल्लंघनों के लिए CCI के 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाली Google की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ट्रिब्यूनल ने सीसीआई को नोटिस जारी कर गूगल की याचिका पर जवाब मांगा है। NCLAT ने याचिका को स्वीकार करते हुए गूगल को बोनाफाइड दिखाने के लिए जुर्माने का 10% जमा करने को कहा। इस बीच ट्रिब्यूनल ने गूगल पर सीसीआई के दंड आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

एनसीएलएटी का यह निर्देश गूगल की ओर से दायर उस याचिका पर आया है। गूगल की ओर से एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस पारिस्थितिकी तंत्र में कई बाजारों में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के सीसीआई के आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में कहा गया था कि यह फैसला भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए एक झटका है और देश में ऐसे उपकरणों को और अधिक महंगा बना देगा। पिछले साल 20 अक्टूबर को सीसीआई ने एंड्रायड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। अक्टूबर के फैसले में सीसीआई ने इंटरनेट कंपनी को विभिन्न अनुचित कारोबारी गतिविधियों से दूर रहने का भी आदेश दिया था। गूगल ने इसे एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी, जो नियामक की ओर से जारी किए गए किसी भी निर्देश या निर्णय या पारित आदेश के खिलाफ एक अपीलीय प्राधिकरण है।

1300 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी जूम, eBay से भी 500 लोग निकाले

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस कंपनी जूम के सीईओ एरिक युआन ने ब्लॉग में लिखा कि 'वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनियमितता और ग्राहकों के इस पर असर के चलते हमें कड़े लेकिन कदम उठाने पड़ रहे हैं।'

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में मंदी का असर दिखने लगा है। यही वजह है कि दुनियाभर में कई कंपनियां अपने यहां स्टाफ की छंटनी करने में जुटी हैं। अब इस लिस्ट में नया नाम टेक कंपनी Zoom का भी जुड़ गया है। बता दें कि जूम ने 1300 कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। यह कंपनी के कुल कार्यबल का 15 फीसदी है। कंपनी के सीईओ एरिक युआन (Eric Yuan) ने कंपनी की वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। एरिक युआन के इस एलान का असर भी दिखा और मंगलवार को नैस्डेक पर जूम के शेयरों में 8 फीसदी की तेजी आई है।

कोरोना महामारी के दौरान कई तकनीकी कंपनियों को गजब की ग्रोथ मिली और जूम भी उनमें से एक थी। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान जब पूरी दुनिया घरों में कैद थी, तब जूम का बिजनेस पर चरम पर था और घरों-ऑफिस वगैरह में जूम का खूब इस्तेमाल हो रहा था। हालांकि अब जब हालात सामान्य हैं तो कंपनी को मंदी का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस कंपनी जूम के सीईओ एरिक युआन ने ब्लॉग में लिखा कि 'वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनियमितता और ग्राहकों के इस पर असर के चलते हमें कड़े लेकिन कदम उठाने पड़ रहे हैं।'

युआन ने लिखा कि 'हम लगातार काम कर रहे हैं ताकि जूम को इसके ग्राहकों के लिए और बेहतर बनाया जा सके लेकिन हमसे भी गलतियां हुई हैं। हमने अपनी टीम की समीक्षा की और ज्यादा वक्त नहीं लिया। हम ये देख रहे हैं कि कारोबार को कैसे ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके'। बता दें कि जूम जिन कर्मचारियों को निकाल रही है, उन्हें चार महीने की सैलरी और हेल्थ कवरेज देने की बात कही गई है। बता दें कि कंपनी के सीईओ एरिक युआन ने भी आने वाले वित्तीय वर्ष में अपनी सैलरी में 98 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है। साथ ही 2023 का कॉरपोरेट बोनस भी ना लेने की बात कही है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के बाद अब दुनियाभर में मंदी का असर बढ़ रहा है और सिर्फ जनवरी माह में ही विभिन्न टेक कंपनियों ने करीब 50 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। डेल ने भी सोमवार को 6600 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का एलान किया है। गूगल ने भी 12 हजार लोगों की छंटनी का एलान किया है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट भी 10 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है।

 # eBay ने भी 500 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की

ई-कॉमर्स फर्म ईबे ने भी मंगलवार को कहा कि वह वैश्विक स्तर पर 500 कर्मचारियों की छंटनी करेगा जो इसके कुल कार्यबल का 4% है। इस घोषणा के बाद सैन जोस कैलिफोर्निया स्थित कंपनी के शेयर आफ्टरमार्केट ट्रेड में लगभग 1% तक मजबूत हो गए। यह बदलाव हमें उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों नई प्रौद्योगिकियों, ग्राहक नवाचारों और प्रमुख बाजारों में निवेश करने और नई भूमिकाएं बनाने के लिए अतिरिक्त स्थान देता है, ईबे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी इयानोन ने कर्मचारियों को भेजे गए एक संदेश में यह बात कही है।

सेवा क्षेत्र का विस्तार 10 महीने के उच्चतम स्तर पर, मांग में वृद्धि का मिला फायदा

नई दिल्ली। एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में अर्थशास्त्र की सहायक निदेशक पॉलियाना डी लीमा ने कहा, दिसंबर में भारतीय सेवा गतिविधि में एक स्वागत योग्य विस्तार देखा गया, जो 2022 के अंत में मांग के लचीलेपन को रेखांकित करता है।

मजबूत मांग और अनुकूल बाजार परिस्थितियों के कारण भारतीय सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर दिसंबर में छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स नवंबर में 56.4 से बढ़कर दिसंबर में 58.5 हो गया, जो 2022 के मध्य के बाद से विस्तार की सबसे मजबूत दर को दर्शाता है। लगातार 17वें महीने यह आंकड़ा तटस्थ 50 की सीमा से ऊपर रहा। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है।

एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में अर्थशास्त्र की सहायक निदेशक पॉलियाना डी लीमा ने कहा, दिसंबर में भारतीय सेवा गतिविधि में एक स्वागत योग्य विस्तार देखा गया, जो 2022 के अंत में मांग के लचीलेपन को रेखांकित करता है।

लीमा ने आगे कहा कि जैसे-जैसे हम 2023 में आगे बढ़ंगे कंपनी उत्पादन के दृष्टिकोण से मजबूत आशावादी संकेत दे रहे हैं। करीब 31 प्रतिशत पैनलिस्टों ने उत्पादन में वृद्धि का अनुमान जताया है, जबकि केवल दो प्रतिशत ने संकुचन का अनुमान जताया है।

थरूर बोले- पीएम मोदी ने भाषण तो अच्छा दिया, लेकिन विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके

एनटीवी न्यूज

नई दिल्ली। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में जोरदार बहस हुई। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सियासी वार के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ-साथ विपक्ष पर जोरदार हमला किया। पल-पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ...

केंद्र सरकार ने राज्यों से पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को एक सवाल के लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि राज्यों को विभिन्न दिशा-निर्देशों के जरिए महिला पुलिस कर्मियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि सभी राज्य सरकारें महिला पुलिस की भागीदारी बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दें। उन्होंने बताया कि ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलेपमेंट (बीपीआरएंडडी) के आंकड़ों के अनुसार एक जनवरी, 2022 तक भारत में सभी स्तरों पर महिला पुलिस कर्मियों की भागीदारी 11.75 प्रतिशत ही है।

मोदी सरकार में एक उद्योगपति के 'अच्छे दिन' आए- कांग्रेस

इससे पहले, कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को 'दिशाहीन' करार देते हुए कहा कि इस सरकार में सिर्फ एक उद्योगपति के अच्छे दिन आए हैं, गरीबों के लिए बुरे दिन आए हैं। बुधवार को सदन में पार्टी के उप नेता गौरव गोगोई ने वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत करते हुए यह भी कहा कि अडाणी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच होनी चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर उपाय नहीं सुझाए हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है, लेकिन बेरोजगारी दर सात प्रतिशत से अधिक है। गोगोई ने कहा कि अगर 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है।

पीएम ने भाषण तो अच्छा दिया लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे सके

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भाषण तो बहुत अच्छा दे दिया लेकिन जो भी विपक्ष द्वारा सवाल पूछे गए थे किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया।

तुम्हारे पांव के नीचे, कोई जमीन नहीं है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं: पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता बोलते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए हमला बोला। पीएम ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने कुछ लिखा है।

प्रधानमंत्री मुद्दे पर बात नहीं कर रहे: राहुल गांधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि पीएम ने किसी मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। अदाणी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को कुछ नहीं बोला। लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी सभी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

पीएम मोदी बोले- मैंने कश्मीर के लाल चौक पर आतंकियों को चुनौती दी थी

पीएम मोदी ने कहा कि जो कभी यहां बैठते थे, वह वहां जाने के बाद भी फेल हुए और देश पास होता गया। मैं भी यात्रा लेकर कश्मीर तक गया था। लाल चौक पर तिरंगा लहराने का संकल्प लिया था। तब आतंकियों ने पोस्टर लगाए थे कि देखते हैं कि किसमें हिम्मत है और किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो यहां आकर तिरंगा लहराता है। तब मैंने कहा था- आतंकी कान खोलकर सुन लें। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सुरक्षा, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट आऊंगा और फैसला लाल चौक पर होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है? जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, तब मीडिया के लोग सवाल करने लगे कि पहले यहां ऐसे नहीं होता था। आज वहां ऐसी शांति है कि वहां चैन से जा सकते हैं। अखबारों में खबर आई थी, जिस पर ध्यान नहीं गया होगा। लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे। उसी समय श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थिएटर हाउसफुल हो गए और अलगाववादी दूर-दूर तक नहीं दिख रहे थे।

मुसीबत के समय 'मोदी' उनके काम आया तो आपके आरोपों पर वे कैसे भरोसा करेंगे

पीएम मोदी ने कहा कि देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए खपा दिया है। देशवासियों का जो मोदी पर भरोसा है, वह इनकी समझ के दायरे से बाहर ही नहीं, समझ के दायरे से काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले देश के 80 करोड़ लोग भरोसा करेंगे? एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के जरिए जब गरीब को राशन मिल जाता है तो वह आपकी झूठी बातों और गलिच्छ आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? जब 11 करोड़ किसानों के खाते में साल में तीन बार सम्मान निधि का पैसा जमा होता हो, वह आप पर भरोसा कैसे करेगा। मुसीबत के समय मोदी उनके काम आया है, आपके आरोपों पर वह कैसे भरोसा करेगा। आपके इन आरोपों को कोटी-कोटी भारतीयों से होकर गुजरना पड़ेगा। कुछ लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो करोड़ों देशवासियों के परिवार का सदस्य है। 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद मेरा सबसे बड़ा कवच है। झूठ और गालियों के शस्त्रों से तुम इस कवच को भेद नहीं सकते।

अरे पहले यह तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है: पीएम मोदी

लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये लोग बिना सिर-पैर की बातें करने के आदी हैं। इस कारण उन्हें ये याद नहीं रहता कि वे खुद कितने विरोधाभासी हो जाते हैं। वे आत्मचिंतन कर खुद के विरोधाभास को भी तो ठीक करें। वे 2014 के बाद से लगातार कर रहे हैं कि भारत कितना कमजोर हो रहा है। अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को धमकाकर फैसला करवा रहा है। अरे पहले यह तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है। कोई भी जीवंत संगठन या व्यवस्था होती है, जो जमीन से जुड़ी होती है तो देश उसका चिंतन करता है, उससे सीखने की कोशिश करता है, अपनी राह भी बदलता रहता है। जो अहंकार में डूबे रहते हैं, जो यह सोचते हैं कि सारा ज्ञान हम ही को है, उन्हें लगता है कि मोदी को गाली देकर हमारा रास्ता निकलेगा।

मां सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है और परिवार सशक्त होता है तो पूरा समाज सशक्त होता है। माताओं-बहनों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। आज आदिवासियों के लिए हमने पानी की व्यवस्था की। हमने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई। पीएम मोदी ने कहा कि हमने माता बहनों के लिए शौचालय की व्यवस्था करवाई।

लोकसभा में लगे मोदी-मोदी के नारे

पीएम मोदी ने कहा कि मुझपर अनाप-शनाप कीचड़ उछालकर ही रास्ता निकलेगा। इतने साल हो गए, वे गलतफहमी पालकर ही बैठे हुए हैं। मोदी पर भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं होता, टीवी पर चमकते चेहरे से पैदा नहीं होता। जीवन खपा दिया है, पल-पल खपा दिया है। पीएम मोदी के इतना कहते ही लोकसभा में मोदी-मोदी के नारे लगने लगे।

कांग्रेस की बर्बादी पर हार्वर्ड नहीं, बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना तय

पीएम मोदी ने कहा कि मैंने कई बार सुना है। यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड का बड़ा क्रेज है। कोरोनाकाल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी। और फिर कल सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात हुई, लेकिन बीते वर्षों में वहां एक बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण स्टडी हुई। उसका विषय था- द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर हारवर्ड नहीं, बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है। और कांग्रेस को डुबाने वाले लोगों पर भी अध्ययन होने वाला है। मैं ऐसे लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा है- तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं?

ईडी का धन्यवाद देना चाहिए कि ईडी ने ही इन लोगों को एक मंच पर ला दिया: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि हमने नौ साल का समय देखा है। उनके दिवालियापन को देखा है। रचनात्मक आलोचना की जगह मजबूरी में आलोचना करने की प्रवृत्ति ने ले ली है। कई लोगों ने उनके सुर में अपने सुर मिला लिए हैं- मिले-तेरा मेरा सुर। इससे तो एक मंच पर आए नहीं, लेकिन इन लोगों को ईडी का धन्यवाद देना चाहिए कि ईडी ने ही इन लोगों को एक मंच पर ला दिया है। जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, वह ईडी ने कर दिया।

लगभग तीन दशकों तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता रही: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगभग तीन दशकों तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता रही। आज हमारे पास एक स्थिर और निर्णायक सरकार है। निर्णायक सरकार हमेशा देश के हित में निर्णय लेने का साहस रखती है...पिछले 9 साल में 90,000 स्टार्टअप सामने आए हैं। स्टार्टअप्स में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं।

पीएम मोदी ने UPA सरकार के वक्त के घोटाले की दिलाई याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय की UPA सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम सभी को याद है उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स में किस तरह से घोटाला हुआ था। उन्होंने कहा कि 2G से लेकर हेलिकॉप्टर घोटाले किस तरह से सामने आए थे। तब कोयला घोटाला भी चर्चा में आ गया था। देश पर कितने ही आतंकी हमले हुए। 2008 के आतंकी हमलों को कोई भूल नहीं सका। उनमें आंख में आंख मिलाकर हमले करने का सामर्थ्य नहीं था। आतंकियों के हौसले बुलंद होते गए। 10 साल तक खून बहता रहा। 2014 के पहले का दशक लॉस्ट डिकेड के रूप में जाना चाहिए।

इनसाइड

पत्रकार की मौत के आरोपी पर चलेगा हत्या का केस, लॉकअप में बंद कैदी हुए फूड प्वाइजनिंग के शिकार

मीडिया संगठनों ने दावा किया कि अंबरकर ने रत्नागिरी जिले के एक पेट्रोल पंप पर पत्रकार को कुचला दिया था। गंभीर हालत में वारिशे को कोल्हापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पत्रकार को कार से कुचलने के मामले में गिरफ्तार आरोपी पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उधर, नालासोपारा पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद नौ लोगों को फूड प्वाइजनिंग की शिकायत होने पर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई मीडिया संगठनों ने पत्रकार शशिकांत वारिशे की मौत की जांच कराने की मांग सरकार से की थी। संगठनों ने दावा किया था कि वारिशे ने स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर पंढरीनाथ अंबरकर के खिलाफ खबर लिखी थी, जिसे प्रस्तावित रत्नागिरी रिफाइनरी परियोजना का समर्थक बताया जाता है। संगठनों ने दावा किया कि अंबरकर ने रत्नागिरी जिले के एक पेट्रोल पंप पर पत्रकार को अपनी कार से कुचल दिया। वारिशे ने मंगलवार को कोल्हापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया।

पत्रकार परिषद के सदस्यों ने सीएम से की जांच की मांग

आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने अंबरकर के खिलाफ प्राथमिकी में धारा 302 (हत्या) जोड़ी है। गिरफ्तार आरोपी को 13 फरवरी तक राजापुर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस हत्या के पीछे की सही वजह की जांच कर रही है। अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद के सदस्यों ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।

रत्नागिरी रिफराइनरी को किया गया रद्द

रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना को तटीय कोंकण में रत्नागिरी जिले के नानर गांव में बनाया जाना प्रस्तावित था। लेकिन 2019 के चुनावों से पहले भाजपा के तत्कालीन गठबंधन सहयोगी शिवसेना के आग्रह पर रद्द कर दिया गया था। एक केंद्रीय मंत्री ने पिछले साल कहा था कि प्रति वर्ष 60 मिलियन मीट्रिक टन तेल रिफाइनरी स्थापित करना दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र होगा और इसके पुनरुद्धार का संकेत दिया था।

पुलिस लॉकअप में बंद नौ लोग हुए फूड प्वाइजनिंग के शिकार

पालघर जिले के नालासोपारा पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद नौ लोगों को फूड प्वाइजनिंग की शिकायत होने पर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का CM योगी ने किया स्वागत, जानें ट्वीट कर क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े दूसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी से 3 हफ्तों के भीतर जवाब देने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला योगी सरकार के लिए काफी राहत लेकर आया है।

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार जारी है। इस चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब राजनीतिक रूप से काफी चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल, पूरा मामला तब उठा जब हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिया था। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े दूसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी से 3 हफ्तों के भीतर जवाब देने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला योगी सरकार के लिए काफी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में योगी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। वहीं, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, रोक के आदेश का स्वागत करता हूँ! इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ो के विरोधी हैं उनको करारा जबाब है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लिया।

सेरोगेसी: क्या सेरोगेट मां से अनुवांशिक रूप से जुड़े होते हैं बच्चे? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी यह दलील

एनटीवी संवाददाता

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सरोगेसी से जन्म लेने वाले बच्चे और सेरोगेट मां के बीच अनुवांशिक संबंध को लेकर जवाब दिया है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया है कि सरोगेसी कानून के मुताबिक सेरोगेट मां बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में आनुवंशिक रूप से नहीं जुड़ सकती। सरकार ने इस कानून का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अपनी युग्मक कोशिका देने वाली ऐसी कोई महिला सरोगेट मां के तौर पर कार्य नहीं करेगी। युग्मक कोशिका वह नर या मादा कोशिका होती है, जो विपरीत लिंग की कोशिका के साथ मिलकर शिशु का निर्माण करती है।

सरकार ने अदालत को अपने जवाब में कहा है कि सेरोगेट मां इससे अलग रहेगी, लेकिन सरोगेसी से जन्म लेने वाला बच्चा निश्चित रूप से संतान की इच्छा रखने वाले दंपती, विधवा या तलाकशुदा से आनुवंशिक तौर पर संबद्ध होगा। इसका अर्थ यह है कि संतान चाहने वाले दंपती पिता शुक्राणु और मां अंडाणु देंगे। जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें एक याचिका में सरोगेसी कानून-2021 और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी कानून-2021 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि इन कानून के प्रावधान निजता के अधिकार और महिलाओं के मां बनने के अधिकार का सीधे-सीधे उल्लंघन है।

सरकार ने कहा है कि पिछले साल मई में सरोगेसी कानून की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड की स्थाना की गई थी। जवाब में सरकार ने कहा है कि इस मामले में राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद स्पष्ट किया गया कि कानून सरोगेट मां को बच्चे के जन्म से आनुवंशिक रूप से जुड़ने की अनुमति नहीं देता। एक याचिका में कहा गया था कि दोनों कानून सरोगेसी कानून के नियमन के उद्देश्य को पूरा करने में नाकाम है। सरोगेसी कानून के तहत व्यावसायिक सरोगेसी पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

क्या सरकार करेगी 6000 रुपये की राशि में इजाफा? 14 लोकसभा सांसदों को मिला ये जवाब

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वस्तुओं की खरीद में सभी भू-धारक किसानों के परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। यह अनुमानित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के अनुरूप हो...

नई दिल्ली। बुधवार को संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान दिए 88 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 11 करोड़ किसानों को साल में तीन बार मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का जिक्र किया। उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही इस राशि में बढ़ोतरी का एलान होगा। वहीं संसद के बजट सत्र में 14 लोकसभा सांसदों ने भी इस निधि को लेकर सवाल पूछे। सांसदों ने पूछा, क्या सरकार का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को भूमिहीन मजदूरों और कृषि श्रमिकों के लिए विस्तारित करने का कोई विचार है। क्या सरकार इस योजना के तहत 6000 रुपये की वर्तमान राशि को बढ़ाने की योजना बना रही है, क्योंकि मुद्रास्फीति कई गुना बढ़ गई है। मंगलवार को पूछे गए इस सवाल का जवाब तो मिला, लेकिन उसमें स्पष्ट तौर से केंद्र सरकार ने यह नहीं बताया कि वह 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' की राशि में इजाफा करने पर विचार कर रही है या नहीं।

इन लोकसभा सांसदों ने पूछा था सवाल

लोकसभा में 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' को लेकर सवाल पूछने वाले सांसदों में रंजीत सिन्हा, हिंदूराव नाईक निम्बालकर, उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, डॉ. हिना विजय कुमार गावीत, दिलीप शइकीया, देवजी पटेल, रीता बहुगुणा जोशी, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, वाई देवेंद्रप्पा, एससी उदासी, डॉ. सुजय विखे पाटील, सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे, सुनील कुमार सिंह और कृष्णपाल सिंह यादव शामिल हैं।

क्या हर साल राशि में वृद्धि करने की योजना है

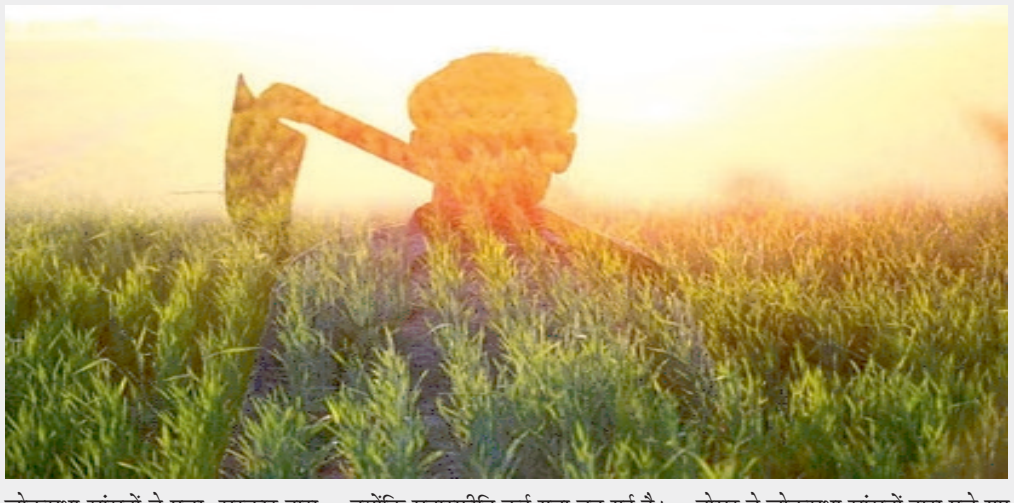

लोकसभा सांसदों ने पूछा, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के माध्यम से किसानों की सहायता के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड में क्या कदम उठाए गए हैं। क्या सरकार का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को भूमिहीन मजदूरों और कृषि श्रमिकों के लिए विस्तारित करने का कोई विचार है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं तो इसके क्या कारण है। क्या सरकार इस योजना के तहत 6000 रुपये की वर्तमान राशि को बढ़ाने की योजना बना रही है, क्योंकि मुद्रास्फीति कई गुना बढ़ गई है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार की पीएम किसान योजना को मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ने और मुद्रास्फीति में वृद्धि के अनुसार हर साल राशि में वृद्धि करने की योजना है। उक्त योजना के शुरू होने के बाद से प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि खर्च की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिया ये जवाब

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा सांसदों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों और अन्य संगत कारकों पर विचार करने के बाद 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एवं गन्ने के लिए उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है। एमएसपी का निर्धारण पूरे देश के लिए किया जाता है न कि क्षेत्र या राज्य विशेष के लिए। हालांकि एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएपीसी द्वारा राज्यों के लिए विशिष्ट मापदंडों पर विचार किया जाता है।

किसानों के परिवारों की वित्तीय जरुरतों को पूरा करना

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वस्तुओं की खरीद में सभी भू-धारक किसानों के परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। यह अनुमानित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के अनुरूप हो। यह सभी किसान परिवारों, जिनके पास कृषि योग्य भूमि है, को उनके भू-धारिता के आकार पर ध्यान दिए बिना कतिपय बहिष्कार मानदंडों के अध्यधीन तीन सम्मान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये की आय सहायता प्रदान करता है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व बुनियादी मानदंड है। इसके अलावा, सरकार की कृषि मूल्य नीति एमएसपी के माध्यम से भी किसानों का समर्थन करती है, जिसे वार्षिक रूप से खरीफ और रबी मौसम के लिए घोषित किया जाता है। इसमें किसानों को प्रतिकूल मुद्रा स्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए अंतर्निहित तंत्र है।